विषय सूची

सत्र-1 (भाग 4) मंगलवार, 23 जून, 2015/आषाढ़ 02, 1937 (शक) अंक-07

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची.....	1-2
2.	निधन संबंधी उल्लेख एवं शोक संवेदना.....	3-9
	(1) श्री इन्द्रराज सिंह (पूर्व सदस्य प्रथम विधान सभा 1993-98)	
	(2) मणिपुर में आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के प्रति संवेदना	
	(3) अफगानिस्तान की संसद पर हुए आतंकी हमले के प्रति शोक संवेदना	
3.	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था.....	9-16
4.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र.....	17
5.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था.....	17-22
6.	मुख्यमंत्री का वक्तव्य.....	22-23
7.	दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 2013-14 के लेखा प्रतिवेदन की प्रति का प्रस्तुतीकरण.....	23
8.	विशेष उल्लेख (नियम-280).....	24-39

9. विधेयक का पुर:स्थापन..... 39-53

(1) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक, 2015

(2) दिल्ली विधान सभा सदस्य अयोग्यता (निवारण) (संशोधन)विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन

(3) दिल्ली नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 का सदन में पुर:स्थापन

10. अल्पकालिक चर्चा..... 53-113

(1) तीनों नगर निगमों की अक्षमता के कारण बढ़ते अवैध निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर

(2) बिजली तथा पानी से उत्पन्न स्थिति पर

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 (भाग 4) मंगलवार, 23 जून, 2015/आषाढ़ 02, 1937 (शक) अंक-07

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।
माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री मोहेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. सुश्री राखी बिड़ला
10. श्री विजेन्द्र गुप्ता
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री इमरान हुसैन
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल
19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री जरनैल सिंह (रा.गा.)

21. श्री जगदीप सिंह
22. श्री जरनैल सिंह (ति. न)
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री गुलाब सिंह
27. श्री कैलाश गहलोत
28. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
29. सुश्री भावना गौड़
30. श्री सुरेन्द्र सिंह
31. श्री विजेन्द्र गर्ग
32. श्री प्रवीन कुमार
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. सरदार अवतार सिंह कालका जी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायणदत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्ला खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओम प्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
51. श्री हाजी इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौधरी फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 (भाग 4) मंगलवार, 23 जून, 2015/आषाढ़ 02, 1937 (शक) अंक-07

सदन अपराह्न 2.02 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत - वन्देमातरम्

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, छठी विधान सभा के बजट सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है, आप दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दे गम्भीरता पूर्वक सदन में उठाएंगे तथा शालीनता पूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग लेकर कार्यवाही संचालन में सहयोग करेंगे। शोक संवेदना के तीन विषय हैं। इसी विधान सभा के प्रथम सदन के सदस्य माननीय श्री इन्द्रराज सिंह जी का देहान्त हो गया था, उनके विषय में मैं जानकारी दे रहा हूं।

निधन संबंधी उल्लेख एवं शोक संवेदना

माननीय सदस्यगण, आपको जानकर अत्यन्त दुख होगा कि पहली विधान सभा 1993-98 के सदस्य श्री इन्द्रराज सिंह जी का 28 मई, 2015 को निधन हो गया। श्री इन्द्रराज जी नरेला विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। एक बहुत ही जुझारू विधायक थे। अपने विधान सभा क्षेत्र एवं दिल्ली के विकास के लिए सदन में पुरजोर ढंग से अपनी बात रखते थे। मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री इन्द्रराज जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में

स्थान दें। व उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम-शान्ति। माननीय मुख्यमंत्री।

माननीय मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्द्रराज सिंह जी का 28 मई को निधन हो गया। इन्द्रराज सिंह जी नरेला विधान सभा क्षेत्र से प्रथम विधान सभा के प्रतिनिधि थे और अपने विधान सभा क्षेत्र में विकास करने के लिए और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी जाने जाते थे। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उनके निधन पर शोक संवेदना प्रस्तुत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शोक बर्दास्त करने की शक्ति दे। ओम शान्ति।

श्री विजेन्द्र गुप्ता जी : अध्यक्ष जी, इन्द्रराज सिंह जी, 1993 में प्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गए नरेला से और काफी प्रभावी नेता थे। ग्रामीण पृष्ठ-भूमि से आते थे। अनुसूचित जाति समाज में वो प्रेरणा दायक स्रोत थे। लेकिन काफी समय से वो बीमार थे, अस्वस्थ थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं हृदय की गहराइयों से संवेदना प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परिवार यह दुख सहन कर सके और उनके जो तमाम अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उनसे प्रेरणा लेकर आज सक्रिय हैं, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि वे उनसे प्रेरणा लेकर समाज में अच्छा काम करते रहें और ईश्वर उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा की शान्ति के लिए मैं अपनी ओर से संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हाल ही में मणिपुर में आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के प्रति संवेदना।

माननीय सदस्यगण, दिनांक 4 जून, 2015 को मणिपुर के चंदेल जिला में 18 सैनिक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। और 11 सैनिक बुरी तरह घायल हुए। सदन इस आतंकवादी हमले की कड़ी निन्दा करता है और भारतीय सेना के सैनिकों की बहादुरी और निडरता का सम्मान करता है। मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शहीदों को अपने श्री चरणों में स्थान दें व उनके परिवार वालों को इस दारूण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शान्ति। माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्यमंत्री जी : अध्यक्ष महोदय, 4 जून को मणिपुर के चंदेल जिले में हमारे 18 बहादुर सैनिक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए और 11 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। हमारी रक्षा करने के लिए व हमारे देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। इस सम्बन्ध में, मैं एक छोटी सी बात यह कहना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली सरकार ने जो भी इन लोगों ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इनकी कुर्बानी प्राईसलैस है। लेकिन समाज की तरफ से व देश की तरफ से हम इनके सम्मान में जैसे दिल्ली सरकार ने यह एलान किया है कि कोई भी सेना का व्यक्ति, सेना का जवान अगर शहीद होगा तो मरणोपरान्त उसके परिवार को दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपये राशि देती है। अगर आप उचित समझें तो दिल्ली विधान सभा की तरफ से उन सरकारों से निवेदन किया जा सकता है जिन-जिन राज्यों से वे थे अथवा केन्द्र सरकार से निवेदन किया जा सकता है कि दिल्ली सरकार की तरज पर अन्य सरकारें भी और केन्द्र सरकार भी जो-जो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवारों को

एक-एक करोड़ रुपये की राशि देकर अगर उनका सम्मान कर सकें तो ये मरणोपरान्त उनके परिवार के लिए देश की तरफ से सम्मान की बात होगी। मैं अपनी और सदन की तरफ से उनके प्रति मरणोपरान्त शोक संवेदना प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता दे।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, 4 जून को मणिपुर के चंदेल जिले में, जो मणिपुर की राजधानी इंफाल से लगभग 118 किलोमीटर दूर है, प्रातः साढ़े आठ बजे सैनिकों के एक काफिले पर 50 आतंकवादी जो आरपीजी लोन्चर्स, तमाम हथियार लेकर घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने कातिलाना हमला किया और इसमें 6 डोगरा इंफनटरी रैजीमेंट के सोल्जर्स थे। इस पूरे मामले को सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीस ने जो यूएनएलएफ और एनएससी - एनके ने जो म्यनमार में सीमा पर अपने कैंप लगाए हुए थे और मारने के बाद वो उस कैंप में भाग गए। लेकिन मैं आज इस सदन के माध्यम से उन तमाम फौजी अफ़सरों को और सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने मुस्तैदी दिखाकर, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की सीमा के पार जाकर, उन कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया और उन कैंपो में 50 से ज्यादा जो आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया और ये एक संदेश पूरी दुनिया को दे दिया कि भारत की फौजें अब चुप रहने वाली नहीं हैं। आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम भारत की सरकार और फौजें उठाएंगी और ये सिद्ध करने के बाद पूरी दुनिया में इसका एक कोगनीजिशन लिया गया। जो 18 सोल्जर्स शहीद हुए और 11 जो घायल है, उनकी स्थिति

भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से जिन सोल्जर्स ने शहादत प्राप्त की है, जो शहीद हो गए देश के लिए, इतना ही कहूंगा कि:

'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा'

अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए इस दुख से वो जल्दी से जल्दी बाहर आएं और हम तो यही कहेंगे कि आपके बलिदान से देश के लगभग 125 करोड़ लोग आज अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सेनाएं त्यागी हैं, तपस्वी हैं और अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा कर रही हैं। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अफगानिस्तान की संसद पर आतंकी हमले के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल दिनांक 22 जून, 2015 को तालिबानी आतंकियों ने संसद के अंदर और बाहर बम विस्फोट किए जिसमें दो नागरिकों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। यह राहत की बात है कि संसद पर हमले में सांसदों तथा सुरक्षा बलों के जवानों को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची और सभी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वास्तव में ये पूरे विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। सदन इसकी कड़ी निंदा करता है तथा हमले में हताहत हुए नागरिकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता है। ओम शांति शांति। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कल अफगानिस्तान में उनकी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह आतंकवादियों ने हमला किया और हमले में वहां के दो नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये एक तरह से पूरे विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर हमला है जिसकी मैं और पूरे सदन की तरफ से हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये शोक सहने की क्षमता दे।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अफगानिस्तान की संसद पर और संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है। जैसा एक दफा हिंदुस्तान में हुआ था उसी तरह की एक शर्मनाक घटना जिसकी मैं अत्यंत कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, ऐसी घटना आतंकवादियों ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की संसद पर की है और उनके पास कार बम, उनके पास हर तरह की दुनिया की एडवांस टैक्नालाजी के तमाम हथियार थे और जब वो एटैक करने गए तो अफगान सिक्योरिटी फोर्सिस ने उनको रोका और सिर्फ रोका ही नहीं, मैं अफगान सिक्योरिटी फोर्सिस की तारीफ करना चाहूंगा कि उनको कॉर्नर किया। एक जगह शरण लेने के लिए मजबूर किया और उसके बाद दोनों तरफ से जो भी गोलाबारी हुई उसमें 6 के 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ये "आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत जवाब अफगान सिक्योरिटी फोर्सिस का" मैं इसको संज्ञान देना चाहूंगा। इस पूरे घटना चक्र में संसद के अंदर किसी भी संसद सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। ये बहुत अच्छी बात

है। लेकिन दुख की बात ये है कि दो लोग एक महिला और एक बच्चा इस हमले के कारण उनकी जान चली गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और अफगानिस्तान के सांसदों के प्रति अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए कि भविष्य में ऐसी घटना फिर से अफगानिस्तान में ना हो, इसका वो प्रयास संसद के अंदर बैठकर सुनिश्चित करें। एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभी खड़े होकर थोड़ी देर मौन रखें।

(सदन में थोड़ी देर मौन रखा गया)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी संवेदना प्रकट करते हुए भारत के सैनिकों के प्रति अपनी भावना से सदन को अवगत कराया है आपने कहा कि प्रत्येक प्रान्त की सरकार को दिल्ली की तर्ज पर यह आग्रह किया जाये कि केन्द्रीय सरकार को भी कि जंग में शहीद हुए सैनिकों को एक-एक करोड़ रुपया उनके परिवार को आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाया जा सके, दिया जाये। अगर सदन इस बात से सहमत है तो मैं सभी प्रान्तों के अध्यक्षों को यह लिखकर भेज सकता हूं कि अपनी सहमति इस पर दें और लोक सभा के अध्यक्षा जी माननीया अध्यक्षा जी को भी लिखकर भेजा जायेगा। सदन अपनी सहमति इस पर दे प्रकट करे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बाकी प्रदेश इस सदन के कार्यवाही का हिस्सा नहीं हो सकते। सदन से प्रस्ताव पारित के बजाय मुख्यमंत्री जी की जो भावनायें हैं अगर वो वहां भेजी जायें तो जो सदन ने व्यक्त की हैं वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि

आप सदन में दिल्ली से संबंधित प्रस्ताव तो पारित के लिये संकल्पबद्ध हैं। भारत की सरकार से आप बातचीत करने के लिए मंत्रीगण, मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जो इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, उसके लिये प्रस्ताव पारित करना, मैं सोचता हूं कि सदन की गरिमा के साथ कहीं न कहीं यह अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रस्ताव नहीं कहा मैंने कहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। उनकी भावनायें सदन में सभी तो सहमत हैं तभी तो अपनी भावनायें उन्होंने व्यक्त की हैं अपने दल की ओर से। हमने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं अपने दल की ओर से। आप भावनायें भेजिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कही न।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां, आप भावनायें भेजिये। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं। लेकिन उसमें थोड़ी सी राजनीति की है। इसलिये हमारा यह आपसे अनुरोध है कि भावनायें भेजना, भावनायें व्यक्त करना यह आपका अधिकार है। लेकिन सदन के पटल पर इस तरह से हमने कभी सुना न देखा। अभी तो हम अध्यक्ष जी, यह जो हमारा 59 में श्री तोमर के मामले में जो विषय है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी ब्यान दें क्योंकि उन्होंने तोमर साहब को क्लीन चीट दी थी। तो हम यही चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी मेरी बात सुनिये...**(व्यवधान)** ओम प्रकाश जी ऐसे नहीं चल पायेगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : पिछले 14 दिनों से जो जेल में हैं माननीय सीएम साहब के संरक्षण के अन्दर डिग्री बनाने का जो कार्य कर रहे थे, आपने उनको सनद भी दी थी कि उनकी डिग्री बिल्कुल ठीक है। वो 14 दिनों से जेल में हैं। कृपया उनके बारे में अपनी बातें बतायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। एक सैकिण्ड मेरी बात समझ लीजिये। यह विषय आपने अपनी बात कह दी। एक सैकिण्ड मेरी बात सुन लीजिये। अभी सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी। 2 मिनट रुक जाइये। मैं जो आपसे कह रहा हूं मेरी बात भी सुन लीजिये। विजेन्द्र जी मैं अभी उस विषय पर नहीं आया हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप के उस विषय पर आने से बात नहीं बनेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी बात कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा यह कहना है कि तोमर के मामले में सी.एम. साहब स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी मदन जी बैठिये आप। ओम प्रकाश जी, विजेन्द्र जी, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुन लीजिये। विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये। ओम प्रकाश जी बैठिये आप आप बैठ जाइये जगदीश जी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं सदन का सम्मान करें। मैं खड़े होकर

बोल सकता हूं। आप बैठिये एक बार। विजेन्द्र जी आप बैठिये एक बार। विजेन्द्र जी, मैं बोल रहा हूं बैठ जाइये। अध्यक्ष खड़े हैं, आपको सम्मान करना चाहिये। मैं खड़े होकर बोलूंगा मुझे 4 घण्टे खड़े रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने प्रण किया है कि सदन को ठीक से चलने दूंगा। आप बैठिये। भाई साहब बैठ जाइये आप। सभी सदस्य बैठिये। यह बहुत गम्भीर विषय है। मैंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा एक सैकिण्ड रुक जाइये। आप अपनी बात बोल चुके हैं। आप हर बात में राजनीति कर रहे हैं। दूसरों को बोलने का मौका दीजिये। आपने अपनी बात रख ली न। यह विषय उन सैनिकों के विषय में था जिनकी सुरक्षा में हम रात को सोते हैं और वो हमारे लिये जाग रहे होते हैं। उनका विचार था, प्रस्ताव नहीं था सदन इस विचार से सहमत है, प्रस्ताव नहीं है **...(व्यवधान)**। विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : पिछले 14-15 दिनों से एक मंत्री जेल में है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : सीएम साहब आपसे निवेदन है कि इस डिग्री काण्ड के बारे में आप कुछ बोलें। मुझे इस विषय में यह कहना है कि सीएम साहब अपना वक्तव्य दें। सीएम साहब अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। आपने जिन डिग्रियों को सत्यापित किया है, वो सारी डिग्री जाली साबित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं सी.एम. साहब से जो आग्रह कर रहे हैं आप उस पर वक्तव्य दीजिये। सी.एम. साहब आपने जिन डिग्रियों को सत्यापित किया है उन डिग्रियों के बनाने का जो कारखाना है,

कोशम्बी में रहते हुए दिल्ली में आपका जो आई कार्ड है कृपया आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप बैठिये। ये जो बोलेंगे वो भी बोलेंगे कैसे रोकूं उनको। आप इनको बैठाइये पहले मैं आ रहा हूं विषय पर। एक सैकिण्ड आपका प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुआ है। नहीं ऐसे नहीं। आप बैठिये पहले **...(व्यवधान)** राखी जी प्लीज। जगदीश जी प्लीज। देखिये मैं सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। सदन का प्रथम दिन है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने के लिये हमारे पास कई चर्चात्मक प्रस्ताव भी आये हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। सदन कुछ निर्णयों पर आगे बढ़ सके। सदन का समय बहुत कीमती है। हमारे पास लिमिटिड समय है। उसका ध्यान रखना है। एक सैकिण्ड, ओम प्रकाश जी दो मिनट रुक जाइये। हम बता देंगे, उसकी चिंता न करें। कार्य स्थगन प्रस्ताव पर मेरी व्यवस्था है। मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियमों 59 के अर्न्तगत एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधानसभा पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 62 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट है कि ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी भी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी ज्यूडिशियल या Quasi-judicial करने वाले किसी Statutory Tribunal और Statutory Authority के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी एक सैकेण्ड। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप देखिये आप जिद कर रहे हैं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात सुन लीजिये। ये बैठिये पहले। पहले आप बैठिये। आप बैठिये। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठ जाइये। विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। हां, आप भी विधायक दल के अध्यक्ष हैं उनके, नेता प्रतिपक्ष है हां ओमप्रकाश जी, मेरा ये कहना है इसमें ये नियम जो बने हुए हैं ये सब चीजों को संविधान के अंतर्गत बने हुए हैं। नहीं, आपके कहने से नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, आप किस ढंग से बात कर रहे हैं आप बात किस ढंग से कर रहे हैं मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, बात करने का आपका तरीका ठीक नहीं है**...(व्यवधान)** आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है**...(व्यवधान)।** दूसरा, विजेन्द्र गुप्ता जी से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर मेरी व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष श्री बिजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 54 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि प्रस्तुत विषय अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है। नियम 54 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व का विषय लिया जाता है तथा मामला पहले ही जांच के लिये विचाराधीन चल रहा है। अतः इस प्रस्ताव को मैं अपनी अनुमति नहीं दे रहा हूं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भ्रष्टाचार इस सरकार के लिये मुद्दा है या नहीं है। श्रीमान सी.एम. साहब आप इसके ऊपर अपना वक्तव्य दें। ये xxx आपके सानिध्य में जो चल रहा था जिसको आपने सत्यापित किया है, उसके बारे में आप कृपया ध्यान दें। उसके बारे में प्रकाश डालें। आप उसके बारे में अपना वक्तव्य दें। इधर बोलिये इधर।

अध्यक्ष महोदय : ये xxx शब्द सब कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तोमर साहब जो विधान परिषद के हमारे, ये सब एसीपी को देंगे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूं। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं। मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। विजेन्द्र जी, मैं चतावनी दे रहा हूं, आप नियम के अंतर्गत आइये ना। इस नियम के अंतर्गत आइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी ने जिस डिग्री को सत्यापित किया है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, मुझे मजबूर मत कीजिये। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं।

---

xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप तो मजबूत हैं...**(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : यह जो नकली डिग्री है कि इस प्रकार की जो नकली डिग्री है भ्रष्टाचार है जिसको सत्यापित श्रीमान सीएम साहब ने किया, उसके ऊपर सीएम साहब अपना वक्तव्य देने की कृपा करें क्या भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा नहीं मानते।

अध्यक्ष महोदय : ओमप्रकाश जी, आपने अपनी बात रख ली। विजेन्द्र जी...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या भ्रष्टाचार दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार जो हो रहा है। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी, आप इस पर अपना वक्तव्य देने की कृपा करें।...**(व्यवधान)** आप बेइमानी करेंगे, रोकेंगे राकेंगे राकेंगे। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है...**(व्यवधान)** जाली डिग्री वालों को भी रोकेंगे। भ्रष्टाचार का हम विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर आप अपना ध्यान दीजिये। आपने जिस डिग्री को सत्यापित किया है अपना बयान दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : महिलाओं पर कुत्ते छोड़ने वाले नहीं बोलेंगे...**(व्यवधान)**

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 2.55 बजे पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए

(xxxx शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये)

सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीप सिंह जी कार्यमंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे। जगदीश सिंह जी, अब बैठिए प्लीज, आपकी बोलने की बारी आएगी। श्री जगदीप सिंह जी, समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण कार्यमंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : सुश्री भावना गौड़।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तोमर के मामले में मुख्यमंत्री बयान नहीं देंगे सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, ये एक तरह से जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाले आज भ्रष्टाचार के मामले में चुप क्यों हैं? हम ये जानना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पीएमबीआर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण श्री दिनेश मोहनिया जी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तोमर के मामले में मुख्यमंत्री बयान दें सदन की कार्यवाही तब तक आगे नहीं चलने दी जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे श्री दिनेश मोहनिया।

---

* पुस्तकालय में संदर्भ सं. R 15143 पर

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जब तक तोमर के मामले में मुख्यमंत्री अपना बयान नहीं देंगे, पूरे मामले पर यहां पर चर्चा नहीं होगी। यहां चर्चा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूं कि उनका ईमान जागे और वो खड़े हो जाएं और कहें मुझे भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं जो मैंने तोमर का समर्थन किया। अगर आप सच्चे हैं तो आप सदन के सामने, मुझे नहीं लगता कि आपको सदन के सामने कोई भी बात कहने में कोई हिचक होनी चाहिए। राजनीति के शिकार क्यों हो रहे हैं आप, अपना बयान दीजिए आप आज तक इस विषय पर क्यों नहीं बोले, आप बोलिए आप बयान दीजिए, आप माफी मांगिए।

...(व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश मोहनिया। ये माईक क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं उनका।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : माईक बन्द किये जा रहे हैं अध्यक्ष जी।

श्री दिनेश मोहनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

---

* पुस्तकालय में संदर्भ सं. 15144 पर

श्री ओम प्रकाश शर्मा : श्रीमान सीएम साहब, आपके दो-दो कानून मंत्री कानून के कठघरे में खड़े हैं। दोनों के ऊपर तरह-तरह के आरोप लगे हैं और आप जो भ्रष्टाचार के...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, आप बैठिये एक बार। विजेन्द्र जी, बैठाइये उनको। बैठाइये। मैं देखता हूं अभी। मैं देखता हूं। आप बैठिये तो सही न। आप पहले बैठिये तो सही। आप बैठ जाइये। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बैठिये शान्तिपूर्वक।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पूर्व कानून मंत्री श्री तोमर जी की डिग्री का मामला उठाया है। अभी कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले ये पूरा मामला उठा था। मैंने लिखित में तोमर साहब की एक्सप्लेनेशन मांगी थी। उन्होंने पूरा जवाब मुझे लिखित में दिया था। उन्होंने उसके सन्दर्भ में मुझे कागज भी दिये थे। उन कागजों को पढ़ने के बाद प्रथम दृष्टया (प्राईमा-फेसायी) मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन उसके बाद अभी पिछले दिनों जब उनकी गिरफ्तारी हुई। पहली चीज तो जिस तरह से गिरफ्तारी की गयी है उसके ऊपर काफी प्रश्न उठे हैं लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी की गयी, उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज की गयी। तुरन्त सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। ...**(व्यवधान)।** एक मिनट,

...(व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गये)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप बैठ जाइये। आप अब नीचे बैठ

जाइये। व्यवधान। व्यवधान। मैं मार्शल से आग्रह कर रहा हूं। ओम प्रकाश जी को बाहर करें। मैं मार्शल से आग्रह कर रहा हूं। ओम प्रकाश जी को बाहर करें। मैं मार्शल से आग्रह कर रहा हूं ओम प्रकाश को बाहर करें। व्यवधान। नहीं बाहर कीजिए इनको

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं बाहर कीजिए इनको। नहीं बाहर कीजिए इनको। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप बैठाइए, आप बैठाइए। मैं विजेन्द्र जी से आग्रह कर रहा हूं आप बैठिए। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक बार विचार कर सकता था लेकिन जिस ढंग से दौड़कर मुख्यमंत्री के सामने वो जाकर खड़े हुए हैं। नहीं आप बिल्कुल नहीं गये और मैंने वो साक्ष्य किया है यह सदन की अवमानना है और मैं इस पर ज्यादा सख्त कदम ले सकता हूं। मैं इस पर नियम के अन्तर्गत और ज्यादा सख्त कदम ले सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं मुलायम हूं। मैं सोच सकता था आपके आग्रह पर, मेरी बात सुन लीजिए। आप बार-बार अवमानना कर रहे सदन की। अध्यक्ष जी खड़े है और आप बिल्कुल शान्त नहीं रहते। आपको इसका भी संज्ञान नहीं रहता कि अध्यक्ष जी खड़े है। एक सेकेण्ड रुक जाइए। अब कोई बीच में कमेंटस न करें। आपसे बातचीत हुई, मैंने 15 मिनट सदन का स्थगन किया आपको चैम्बर में बुलाया बैठकर बातचीत की। बातचीत होने के बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं ने संज्ञान

लिया। मुझे भी कहलवाकर भेजा और उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री किसी भी सदन में विजेन्द्र जी, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। एक सेकेण्ड मेरी बात सुन लीजिए वो सारा दृश्य सामने ले लीजिए मेरे पास सेक्रेटरी साहब आये कि मुख्यमंत्री जी को बुलाया। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। मैंने आपसे आग्रह किया कि बैठिए फिर भी आप बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे। इन-बिटविन मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हो गये और उन्होंने बोलना आरंभ किया और बोल रहे थे इन-बिटविन ओम प्रकाश जी का जिस प्रकार व्यवहार रहता है बार-बार। मुख्यमंत्री बोल रहे है, उत्तर दे रहे हैं, फिर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे आग्रह करने पर भी वो नहीं बैठ रहे हैं। मुझे बोलना पड़ा। बोलने के बाद वो जिस ढंग से दौड़कर गये मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के सामने इससे बड़ा शर्मनाक दृश्य नहीं हो सकता किसी भी सदन के लिए। ये उचित नहीं है। ये किसी भी सदन के सदस्य के लिए उचित नहीं है। मैं इस सदन की कार्यवाही में खड़ा हूं मत बोलिए आप प्लीज। देखिए मैंने आपसे आग्रह वहां भी किया था कि ओम प्रकाश जी को थोड़ा समझाइए, बैठाकर समझाइए। मैंने बुलाया भी, बात भी की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं नहीं जानता। ना मैं कह सकता हूं। मैं उनको निवेदन कर सकता हूं आग्रह कर सकता हूं। सदन की गरिमा बनाए रखना मेरा दायित्व है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम बैठकर बात कर लेंगे लेकिन अब इस विषय को जिस ढंग से उन्होंने किया है, कानून के अन्तर्गत संविधान के अन्तर्गत उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। वेल में आ गये, कोई बात नहीं वेल में आने के बाद सीधा सीना

तानकर मुख्यमंत्री जी के सामने, नहीं ऐसे तरीका नहीं। यह तरीका नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि जब कुछ महीने पहले यह मामला उठा था तो मैंने उनकी लिखित एक्सप्लेनेशन मांगी थी। उन्होंने मुझे लिखित में जवाब दिया था। उन्होंने मुझे कुछ कागज भेजे उन कागजों को पढ़ने के बाद पहली नजर में ऐसा लगता था कि कोई गड़बड़ नहीं है। उसके कुछ हफ्तों के बाद जब एक दिन उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी में भेजा। हमने तुरन्त उनका इस्तीफा स्वीकार किया। क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार राजनीति के लिए आयी है। हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था देने के लिए आयी है। हम किसी भी हालत में गलत काम बर्दाश्त नहीं करने वाले। न हमारी किसी से रिश्तेदारी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं न मेरी किसी एमएलए से रिश्तेदारी है न किसी मंत्री से रिश्तेदारी है हम क्यों गलत काम बर्दाश्त करेंगे? उस दिन हमने तुरन्त उनका इस्तीफा स्वीकार किया। उनको मंत्रिमण्डल से हटाया और उसके बाद जो पुलिस जांच कर रही है और जो मीडिया में आ रहा है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, लेकिन अगर वह सब सच है तो मुझे लगता है कि मुझे धोखे में रखा गया था। तब उन्होंने जो जवाब, दिया जो कागज मुझे दिये इसका मतलब मुझे धोखे में रखा गया था। अगर वह सच है, तो जो हो रहा है लेकिन मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी सजा देगी वह सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मामले के सामने आते ही जैसे हमने उन्हें मंत्रिमण्डल से हटा दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आप उनको बोलने दीजिए।

मुख्यमंत्री : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता चाहता हूं कि जैसे मुझे धोखे में रखा गया ऐसे ही लगता है उनके मंत्री भी प्रधानमंत्री जी को धोखे में रख रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को जिन जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं जैसे सुषमा स्वराज जी है, वसुंधरा राजे जी है, उन सबको मंत्रिमंडल से हटाकर और उनकी भी निष्पक्ष जांच करवायी जाए और उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आपकी बात पूरी हो गयी है। विजेन्द्र जी आप जो मुख्यमंत्री जी से बयान चाहते थे, वो उन्होंने दे दिया। विजेन्द्र जी अब बैठिए। सदन पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात मैं श्री सतेन्द्र जैन जी, ऊर्जा मंत्री...**(व्यवधान)** विजेन्द्र जी आप बैठिये अब, आप बैठ जाइये। चलिये सतेन्द्र जैन जी ऊर्जा मंत्री नियमावली प्रतिवेदनों की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखें। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। अलका जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 2013-14 के लेखा प्रतिवेदन की प्रति का प्रस्तुतीकरण

श्री सतेन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2013-14 हेतु दिल्ली परिवहन निगम का पृथक लेखा प्रतिवेदन की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन के पटल प्रस्तुत करता हूं। साथ में जो विलम्ब हुआ उसकी प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2013 और 2014 हेतु दिल्ली परिवहन निगम वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की सम्पूर्ण अंग्रेजी और हिन्दी प्रति सदन के पटल प्रस्तुत करता हूं धन्यवाद।*

*प्रस्तकालय में संदर्भ सं. R-15145-147 पर

विशेष उल्लेख (नियम 280)

अध्यक्ष महोदय : नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपने क्षेत्र की जो आज समस्या रखने जा रहा हूं वो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है जिस जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं। उस जंगपुरा विधान सभा में दो अहम सड़कें हैं: एक तो मथुरा रोड और दूसरा है रिंग रोड। इन दोनों सड़कों पर दिन के समय में और स्पेशली पीक ऑवर में इतना भयंकर ट्रैफिक लगा रहता है कि जो भी वहां से गुजरता है, उसे घण्टों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आश्रम से जहां की आबादी लगभग चार से पांच हजार है, जब वहां पर रहने वाले उस रिंग रोड या मथुरा रोड को यूज करते है, तब उन्हें भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा...

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी, एक सेकेण्ड मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरी माननीय सदस्यों से मीडिया के बन्धुओं से प्रार्थना है थोड़ा बातचीत न करें ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठे बन्धुओं से प्रार्थना है कृपया शांति बनाए रखें। चलिए प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ दिन पहले मेरे क्षेत्र में एक एक्सीडेन्ट हो गया आश्रम चौक पर। गंभीर अवस्था में उस 21 वर्षीय बालक को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन मथुरा रोड से लेकर सराय काले खां तक कोई भी कट न होने के कारण उस बच्चे की रास्ते में ही डेथ हो

गयी। अभिप्राय: यह है कि आश्रम चौक से सराय काले खां तक एक भी कट न होने के कारण काफी घण्टों जाम लग जाता है। जिसके कारण कई लोग इस हादसे के शिकार होते है और स्कूल बसें सुबह के टाइम में कई सारी स्कूल बसें डिले होती है, शाम के टाइम में भी कई लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय मेरी एक गुजारिश है कि जिस तरह से बाकी के फ्लाईओवर के नीचे से पैसेज दिया जाता है और बाकी फ्लाईओवर में क्लीनर पैसेज दिया जाता है, रेजिडेंस के लिए उसी तरीके से आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन डी.एन.डी. फ्लाईओवर तक किया जाए ताकि आश्रम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी एक क्लीयर पैसेज मिले और कई लोगों की जान बच सकें। अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में एक बारापूला एक्सटेंशन फ्लाईओवर है जिसका अभी निर्माण चालू हुआ था एक भाग का जिसके कारण सिद्धार्थ एक्सटेंशन एक जगह है, जहां कि बहुत विकट परिस्थिति में वहां के लोग आ गए थे क्योंकि एक रोड बन्द हो रही थी तो उनके और मेरे आग्रह पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सतेन्द्र जैन जी ने तुरन्त एक मीटिंग बुलाई और उस बारापूला एक्सटेंशन फ्लाईओवर का नक्शा डिजाइन जो एक्सचेंज किया गया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री राखी बिरला जी।

सुश्री राखी बिरला : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय साहब, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। आज जिस विषय को मैं सदन के सामने रख

रही हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरी दिल्ली की जनता इससे जुड़ी है। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी का आंदोलन किया था तो उस दौरान हमने जनता से अपील की थी कि वो बिजली और पानी के बिल न भरें। जिसकी वजह से कई लोगों के बिल जमा हो गये हैं, बहुत कई हजारों के हो गये हैं। बिजली विभाग ने किश्तों के माध्यम से डिबेट देके लोगों को डिस्काउंट दिया है लोगों को निजात मिली है बिजली के बिलों से लेकिन पानी के बिलों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। न तो जल विभाग की ओर से कोई रिबेट दी जा रही है न कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान है। आए दिन मेरे विधानसभा दफ्तर में लोग अपने पानी के बिलों की समस्या को लेकर आते हैं। बार-बार माननीय मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, जल बोर्ड के जो चेयरमेन हैं मैं बार-बार अनुरोध कर चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय एक बार पुनः आपके माध्यम से इस बात का अनुरोध करना चाहती हूं कि पानी के जो बढ़े हुए बिलों की समस्या है कृपया इसपर ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा जो जल बोर्ड की एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये तीन से चार साल का बिल इकट्ठा दे रहे हैं जनता को। अगर जनता को हर महीने बिल मिले या साठ दिन के अंदर बिल मिले तो शायद वो आसानी से अपना बिल भर पायेंगे। लेकिन अगर तीन-तीन चार-चार साल का बिल एक साथ जनता पर थोपा जायेगा तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी है। मेरे क्षेत्र में मोस्ट परोबेबली गरीब जनता रहती है, वो अपने गहने बेचकर घर गिरवी रखकर मजबूर है पानी का बिल भरने के लिए। अब हमने यहां तक जनता को कह दिया है कि जब तक जल बोर्ड की तरफ से कोई रिबेट नहीं मिलती, कोई डिसकाउंट नहीं

मिलता, वो लोग अपने बिल न भरें। मैं कई बार बिजली पानी के बिल दे चुकी हूं उप मुख्यमंत्री साहब को भी, मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करना चाहती हूं और एक बार पुनः ये बिल मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि इन्हें अपने संज्ञान में लें क्योंकि बहुत ही बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली वासियों की ये समस्या है सिर्फ मंगोलपुरी विधानसभा की ये समस्या नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि माननीय उप मुख्यमंत्री साहब और जल बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा जी ये इसको इम्पोर्टेंट बेसिस पर इस के ऊपर ध्यान देंगे और कपिल मिश्र जी को बधाई कि वो मंत्री बने हैं, हमारे नये कानून मंत्री तो आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : मैं आपका ध्यान पानी के बिलों की तरफ जैसा अभी बहन जी ने कहा पानी की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में गरीब लोगों की संख्या काफी है जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनके पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जिसे देखकर दिल कांपता है। दिल्ली जल बोर्ड क्या अत्याचार कर रहा है एक आध व्यक्ति के पचास-पचास हजार एक-एक लाख से ऊपर के पानी के बिल आ रहे हैं पानी के बिल देखकर हैरानी होती है। दिल्ली जल बोर्ड किस मापदंड पर पानी के बिल बना रहा है। पानी आता नहीं खाली बिल ही समय पर आ रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति ऐसे गलत बिलों का भुगतान कहां से करेगा एक मकान में एक व्यक्ति ने छोटी सी दुकान बना ली है कि पूरे मकान का 10 परसेंट हिस्सा भी नहीं है। उसकी दुकान में पानी का कनैक्शन भी नहीं है तो भी पूरे मकान का बिल

कमर्शियल कर देते हैं और लाखों रुपये का बिल बनाकर भेज देते हैं ये कहां का इंसाफ है उस मकान का पानी का बिल अगर दुकान में पानी इस्तेमाल होता है तो प्रतिशत के हिसाब से आना चाहिए। जल बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है। जिससे पूरी दिल्ली की जनता परेशान है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जल बोर्ड की इस मनमानी को खत्म करें तथा दिल्ली की जनता को इन गलत बिलों से राहत दिलायें तथा स्कीम चलाई जाये इन गलत बिलों पर जिससे मनमाने चार्ज लगे हुए हैं उन पर 80 परसेंट की छूट का ऐलान करें जिससे दिल्ली की गरीब जनता को राहत मिले।

मेरे कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में पानी आने का समय भी बहुत कम है। अत: आपसे प्रार्थना है कि पानी आने का समय सुबह व शाम का बढ़ाया जाये। झुग्गी झोपड़ियों में पानी का प्रबंध कराया जाये, पानी के प्याऊ भी लगाये जायें। अध्यक्ष महोदय, आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं एक बड़े ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रख रहा हूं। अभी आप को सब लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल की गई। इस हड़ताल के कारण हर विधानसभा क्षेत्र में और पूरी दिल्ली के अंदर एक हा-हाकार की स्थिति मच गई। सभी विधायकों के घरों पर उनके कार्यालयों पर कूड़ा फैंका गया। जिससे एक माहौल बड़ा खराब हो गया और जब कि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि न ही हमारी सरकार इस मामले पर राजनैतिक बात कर

रही थी। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं सफाई कर्मचारियों की मांग जायज थी हम भी उस बात से सहमत थे लेकिन हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने रामलीला ग्राउंड के अंदर कर्मचारियों को 31 मई तक का वेतन देने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद भी उसको राजनैतिक मुद्दा बनाया गया। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि एमसीडी के अंदर सरकार किसकी है। एमसीडी के अंदर जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और इस बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया इसके बारे में। मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक ऐसी कोई एजेंसी बनाई जाए जिसमें एक नई रिक्रूटमेंट की जाये और जिसके अंदर ऐसी अगर कोई इश्यू आए तो सफाई कर्मचारियों के लिए एजेंसी बना के और जो भी अपने क्षेत्र के लोग हैं ऐसी जो बात होती है वो न की जाये। ये मेरा प्रस्ताव है इस सदन के अंदर। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो भी सफाई कर्मचारी हैं, आज भी बहुत जगह कूड़ा वहां पर फैला हुआ है। आज भी सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा नहीं उठाया। इसके लिए जो भी दिल्ली के अंदर जो भी बीजेपी की सरकार है इनको सीधा इनसे जवाब मांगा जाये कि अगर आप लोग यहां एमसीडी के लोग आप यदि सत्ता में अंदर हैं तो क्यों नहीं सफाई की व्यवस्था आप लोग अपने हाथ में लेते हैं और अगर ये नहीं कर पायें तो दिल्ली सरकार इनको सीधा टेक ओवर कर ले और सफाई व्यवस्था की जो भी जिम्मेदारी वो दिल्ली सरकार ले, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं भाई कपिल जी को भी बधाई देना चाहता हूं उसको और सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में नये मंत्री बने हैं उनका हार्दिक स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : Respected Mr. Speaker, Sir, firstly, I thank you for giving me this opportunity and I would like to bring forth peculiar situation that is happening in East Delhi. There are so many schools in East Delhi who have been probably allotted land at a very subsidized rate by past Governments through DDA. They were supposed to give admissions to the EWS category people. They have made a business out of it and they have also encroached upon adjacent or nearby lands or paths and I have, actually, made a list of such schools. I'll give it to you later on who have been allotted for example, a two acre piece of land and they had an adjacent land of two acres another land and they have encroached upon and they are using it within the premises of the school. Who is responsible for it? Is the institution who has encroached upon this land only responsible for it or the people in the authority? Because land primarily comes under DDA, are people in the authority responsible for it, or the past Governments, either Delhi Government or the Central Government, are they included in that? What is the procedure and the Plan of Action that we can get this land back from these schools or other institutions? What is the penalty for such institutions.? What is the penalty for the authority and the governments who have facilitated such acts? सर, आज की तारीख में दिल्ली की जनता को दिल्ली के लिए लैंड, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी से खरीदना पड़ता है यहां पर करोड़ों-करोड़ों रुपये का

लैंड फ्री फण्ड में उनको दे रखा है वो उसको यूज कर रहे हैं स्कूल के अंदर ये ऐसा क्यों? इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि एक एक्शन लिया जाये। डी.डी.ए. उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है उसके बारे में पता किया जाये। ये लैंड दिल्ली की जनता को वापिस मिलना चाहिए। ये लैंड इस तरीके से एंक्रोच करके स्कूल वाले यूज करते हैं और उसके बावजूद आस-पास की जनता को कोई उसकी बेनीफिट नहीं होता वो लोग यूज भी नहीं कर पाते उस लैंड को। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसके लिए आपसे ये रिकवेस्ट है कि डी डी ए के वाइस चेयरमेन से, उनको तलब करके इसके बारे में पता किया जाये तथा इसपर एक्शन लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि नियम 280 के तहत आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का अवसर दिया। उससे पहले मैं श्री कपिल मिश्रा जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आपके कन्धों पर बड़ी जिम्मेदारी आई हैं मेरी शुभकामनाएं, पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा।

अध्यक्ष जी अभी मुम्बई में अवैध शराब और जिस तरीके से 102 मौतें हुईं। 40 के करीब अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये अवैध शराब की जिस तरीके से बिक्री हो रही है गंभीरता से इसकी तरफ आपका और पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, मैं अभी कुछ समय पहले एक मौहल्ला सभा के तहत कूंचा मुरतल खान जो मेरी विधान सभा में आता है, वहां मोहल्ला सभाओं में महिलाओं ने इस विषय को उठाया कि वहां पर एक अवैध कॉलोनी है मद्रासी कॉलोनी हैमिल्टन रोड पर, वहां बताया महिलाओं ने मोहल्ला सभाओं

में कि यहां पर अवैध शराब बनती भी है और बिकती भी है और सब कुछ दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे होता है। मैं ये कहूंगी कि जो कुछ भी अभी महाराष्ट्र में घटित हुआ है, हमें उससे सबक लेने की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि इस तरह की कोई भी अवैध शराब की बिक्री की वजह से इस तरह कोई हादसे से सबक लेते हुए हमें बचना होगा। मैं आपको सिर्फ जुलाई का आंकड़ा बता रही हूं। जुलाई 2009 में गुजरात जहां पर बीजेपी की सरकार है, जो शराब जो ड्राई स्टेट है। शराब पर बैन है उसके बावजूद अवैध शराब से 127 मौतें होती हैं ये 2009 का जुलाई का गुजरात का आंकड़ा कहता है। कहीं न कहीं मुझे इसमें लापरवाही दिखी, तभी ऐसा हुआ। दिसम्बर 2011 में दूसरा बड़ा हादसा हुआ पश्चिम बंगाल के परगना शहर में 170 लोगों की मौत हुई वो इसी अवैध शराब और गंदी शराब से हुई है। अभी ये तीसरा हादसा महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी की सरकार है 102 मौतें होती हैं। मैंने इस मोहल्ला सभा के बाद खुद डीसीपी पुलिस को फोन किया को और इसकी उनको सूचना दी उन्होंने मुझे कहा कि वो अपने थाना लाहौरी गेट पर लगता था जहां मेरी मीटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा कि वे एसएचओ को भेजते हैं। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया पर वो एसएचओ हमें वहां आकर मिले नहीं और वहां के लोगों ने कहा कि यहां पर सबक मिलीभगत से लाखों रुपये का अवैध शराब बनाने व बेचने का धन्धा चल रहा है, आप खुद देरी मत करिये अभी चलिए और चलकर देखिये और मैं जब अपने वॉलियेंटर के साथ जब वहां पर गई थोड़ी दूर पर खड़े इसलिए हो गई कि लोगों ने कहा कि आपको पहचान जाएंगे इसलिए हम इसको कैद नहीं कर पाएंगे इस अपराध को अभी भी होते हुए तो वहां के लोग वहां पर गये मैं थोड़ी दूरी से खुद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई वीडियो में

आया जिसको मैंने हमारे डीसीपी हैं मधु वर्मा जी, उन के साथ शेयर किया। एसएचओ के साथ शेयर किया। जिसमें शराब को अवैध तरीके से सरेआम मद्रासी कॉलोनी के बाद हैमिल्टन रोड पर भेजते हुए वीडियो रिकॉर्ड में किया गया और उसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप अवैध तरीकों से शराब बेचते हुए पकड़े भी जाते हैं तो बच्चों के ऊपर कार्रवाई होगी न कि किसी बड़े के ऊपर, जो उनको लगता है छूटकर आ जाएंगे और सख्त सजाएं नहीं होंगी। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष जी केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी मजनू का टीला, ये सिविल रोड थाने में आता है, नवाब गंज जो है थाना यमुना बाजार जहां पर बच्चों को सोल्यूशन पीते हुए, नशा करते हुए आप सरेआम रोजाना उनको देख सकते हैं। मैं ये कह रही हूं अध्यक्ष जी सिर्फ निवेदन कर रही हूं पुलिस की जानकारी में ये सब अपराध हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर अध्यक्ष जी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मुझे इस बात का डर है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी राजनीति बहुत जल्द हो जाती है। जहां महाराष्ट्रा में मैं कहूंगी 102 मौतें हुईं, जहां गुजरात की अगर मैं बात कहूं इतनी मौतें सौ से ऊपर मौतें गुजरात में हुईं। वहां की पुलिस उनके अधीन थी यहां की पुलिस आपके अधीन नहीं है। उसके बावजूद भी मैं कहूंगी इसे गंभीरता से लें ताकि इस तरह के हादसे को हम होने से रोक पाएं। मैं इसी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती थी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी। (अनुपस्थित) श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करता हूं कि

आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जगप्रवेश चन्द्र हॉस्पिटल उत्तर पूर्वी जिले में दिल्ली सरकार का एक प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में मरीजों की चिकित्सा सुविधा हेतु 200 बैड हैं। साथ ही कुछ विभागों के बाह्य रोगी सुविधा या ओपीडी भी उपलब्ध है परन्तु अध्यक्ष महोदय क्षेत्रीय जनसंख्या अधिक होने के कारण यहां मरीजों की संख्या ज्यादा है। इस दबाव के चलते सभी मरीजों को बैड की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती जिससे डॉक्टरों उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। क्षेत्र की गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर जनता जो इस हॉस्पिटल में आने जाने का खर्चा उठा नहीं पाती साथ ही उन हॉस्पिटल पर चिकित्सा दबाव पड़ता है जिससे कई बार मरीजों के रिश्तेदारों व डॉक्टरों के बीच हाथापाई व कहासुनी की घटना होती रहती है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय कई बार मरीजों को हॉस्पिटल में सुविधा न मिलने के कारण आपात स्थिति में दूसरी जगह भेजा जाता है तो रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाती है। अत: आपसे अनुरोध है कि जगप्रवेश चन्द्र हॉस्पिटल में बैडों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 की जाए क्योंकि यहां पर जगह काफी है। वहां पर और बन सकती है। अन्य मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं आपका ध्यान घोंण्डा में कई वर्षों से चल रही डिस्पेंसरी की तरफ दिलाना चाहता हूं इस डिस्पेंसरी में काफी जगह उपलब्ध है। इस डिस्पेंसरी में जच्चा बच्चा कैम्प के साथ मरीजों के लिए चिकित्सा बैड की सुविधा भी दी जा सकती है ताकि क्षेत्रीय जनता को उचित चिकित्सा लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान भजनपुरा डिस्पेंसरी चौक स्थित डिस्पेंसरी की तरफ दिलाना चाहता हूं यह डिस्पेंसरी पिछले लगभग 30

वर्षों से क्षेत्रीय जनता को चिकित्सा लाभ दे रही थी परन्तु जर्जर हालत व अपर्याप्त सुविधा के चलते इसे लगभग 10 वर्ष पहले बन्द कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय यह डिस्पेंसरी मेरी विधानसभा क्षेत्र के पास की एकमात्र डिस्पेंसरी थी जिसके महत्व का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जगह को डिस्पेंसरी चौक के नाम से ही जाना जाता है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस डिस्पेंसरी का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी विधानसभा में जनता के विश्वास को कायम रखते हुए अपने क्षेत्र में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूं ताकि दिल्ली की जनता जिसने बड़े विश्वास व भरोसे से आम आदमी पार्टी को प्रचण्ड बहुमत दिया है, उसके इस विश्वास व भरोसे को कायम रखा जा सके धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री सरिता सिंह जी।

सुश्री सरिता सिंह : स्पीकर सर आज मैं जिस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह दिल्ली पुलिस का आतंक व दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। यह केवल रोहताश नगर का मुद्दा नहीं है ये पूरी दिल्ली का मुद्दा है। मैं अपने यहां पिछले 25 दिनों में हुए हादसों के बारे में बताना चाहती हूं। दिन दहाड़े एस.के. जनरल नाम के एक व्यक्ति पर गोली चलाई जाती है। करोड़ों रुपये की डकैती की जाती है डीसीपी ज्वाइंट सीपी सभी मौके पर आते हैं उनको सीसीटीवी फुटेज दिया जाता है उनको सारे सबूत दिये जाते हैं। पर आज 25 दिन हो गये आज तक एक भी सुराग या एक भी दोषी दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हद तो तब हो गई जब दो दिन पहले मानसरोवर

पार्क एक एरिया है मेरे यहां पर वहां पर एक बुजर्ग महिला का एक्सीडेंट हुआ एक ड्राईवर ने ड्रिंक किया हुआ था उसके द्वारा उनकी हत्या की जाती है वहां के लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिया कि भाई साहब ये लो। ये वो है जिन्होंने एक्सीडेंट किया था जिन्होंने मारा था। दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए उस हत्यारे को छोड़ दिया कि हमारे पास स्टॉफ नहीं है। तो हम इस महिला का पोस्टमार्टम करवायें कि हम इस मुजलिम को अन्दर करें। ये डीसीपी के वर्ड्स थे। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं यहां पर हम केवल 70 लोग नहीं बैठे, ये दो करोड़ जनता की आवाज है और बार-बार जब जनता हमारे पास में आती है तो हम उन्हें ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती पर जनता ये नहीं समझती। जनता को ये चाहिए कि दिल्ली पुलिस काम कब करेगी।

परसों की बात है एक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति ने शाहदरा चौक पर घूस लेते हुए पुलिस को पकड़ा, स्टिंग ऑपरेशन किया। जब वो अपने एसएचओ के पास गया कि ये स्टिंग ऑपरेशन आपके हवलदार का है। जहां वो घूस ले रहा था एसएचओ ने उस लड़के को थाने के अन्दर बन्द किया और ये कहा कि तुम्हारे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, तुम्हारे ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी। इस तरह से दिल्ली पुलिस क्या दिल्ली की जनता को डराना चाहती है, क्या करना चाहती है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। दिल्ली पुलिस को इस सदन में हम बार-बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को इस सदन के लिए जवाबदेह बनाया जाए। हम कब तक लोगों से ये बोलते रहेंगे कि दिल्ली पुलिस का काम हम नहीं कर सकते, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो आपसे यह अनुरोध है कि दिल्ली पुलिस के कमिशनर को समन किया जाए, उनको यहां बुलाया जाए और उनसे ये पूछा

जाए कि दिल्ली की जनता के साथ ये अत्याचार ये अन्याय वो क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय नजफगढ़, मटियाला, उत्तम नगर, विकासपुर, मुण्डका ये आठ दस विधानसभाओं से लोग हरियाणा की तरफ जाते हैं और मैं ये कहूं कि मानेसर व गुड़गांव के औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी के लिए रोजाना लाखों हजारों की संख्या में लोग यहां से जाते हैं और इन सभी का रूट अगर मैं ये कहूं कि द्वारका से होते हुए जाता है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है मैं अपने इस वक्तव्य में ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर का ध्यान चाहूंगा कि वो इस बात को गंभीरता से लें। हमारे परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय जी, मैं आपसे चाहता हूं कि द्वारका से सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से मेट्रो का विस्तार कापसहेड़ा बार्डर होते हुए इफ्को चौक गुड़गांव तक किया जाए। इससे लाखों लोगों को सुविधा होगी और अगर आप रोजाना ट्रैफिक जाम की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। सेक्टर 21 के अंडर पास पर रोजाना की स्थिति ये है कि हरियाणा झज्झर शहर तक के लोग रोजाना द्वारका होते हुए गुड़गांव पहुंचते हैं। नरेला मुण्डका तक के लोग रोजाना गुड़गांव पहुंचते हैं। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और ढ़ाई से तीन तीन घण्टे तक सुबह के समय वहां पर ट्रेफिक जाम रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली मैट्रो के साथ बैठकर इस विषय में कोई ठोस कदम उठायें। साथ में पूरी दिल्ली की अगर मैं बात करूं। मोनो रेल के बारे में मैंने कुछ दिन पहले

अखबारों में भी पढ़ा था कि माननीय परिवहन मंत्री और दिल्ली मैट्रो आपस में बात करके आपस में कोई संज्ञान ले सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा कदम दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, जो कि आने वाले समय में बहुत ही बुरी तरह से चरमरा सकती है, जिस तरह के हालात आप आज सड़कों पर देखते हैं। अगर मोनो रेल से पूरी कॉलोनियों को जोड़ दिया जाये, खास तौर से द्वारका के अंदर, लोकल ट्रान्सपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी तरह से, किसी भी सैक्टर में जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की परिवहन की बसों की वहां पर आवाजाही नहीं है। जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी समस्या लोकल ट्रान्सपोर्ट की है। मोनो रेल का विस्तार वहां पर बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि वहां की सभी सड़कें 24 मीटर से ऊपर की हैं। ये बहुत आसानी से द्वारका में मोनो रेल का विस्तार किया जा सकता है और जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सरदार जरनैल सिंह जी (रा.गा.)

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है। चलिए नहीं लगाया, कोई बात नहीं। माननीय सदस्य का निवेदन मेरे पास आया है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि नियम 280 के अन्तर्गत आप अपने क्षेत्र की समस्या को बड़े गंभीर तरीके से रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए नोटिस देने का समय 11 बजे पूर्वाह्न तक होता है। प्रत्येक दिन 11 बजे से पूर्व आप अपना रिक्वेस्ट

दे सकते हैं। 11 बजे के बाद की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जायेगी। इसलिए मैं संदीप जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपना नोटिस कल 11 बजे से पूर्व दे दीजिए। बाकी के 5 दिन भी आप ये नोटिस दे सकते हैं। अब मैं विधेयक के पुरस्थापन के निमित्त माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2015 को सदन में पुरस्थापित करने की अनुमति मांगे।

विधेयक का पुर:स्थापन

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली में झुग्गियों की स्थिति और उस दिशा में जो सरकार काम कर रही है, उससे संबंधित दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2015 को सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी बात इस विधेयक के संबंध में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में झुग्गियां, में कहूं कि झुग्गियां दिल्ली का एक बहुत बड़ा सच है। हम देश की राजनधानी में रह रहे हैं और देश की राजधानी में दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी जो देश के कोने कोने से आई है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर बहुत बड़े सपनों के साथ, अभावों के साथ, संघर्षों के साथ यहां आकर रह रहे हैं, वह झुग्गियों में बसती है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा झुग्गियों में बसता है। कहीं मैं देखता हूं कि हमारी व्यवस्था में इन झुग्गियों को हमेशा दोयम दर्जे के नागरिकों की हैसियत से देखा जाता है। यह बहुत बड़ी पीड़ा है। झुग्गियों में कौन रह रहा है और क्यों रह रहा है, यह

थोड़ी सी बात इस पर रखते हुए संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूं। झुग्गियों में वे लोग क्यों रह रहे हैं या कौन लोग हैं उसमें हम बहुत खुशी खुशी किसी शादी में जाते हैं, वहां पर पूरे जश्न का माहौल होता है और उस जश्न के माहौल के बीच एक व्यक्ति जो वहां बाजा बजा रहा होता है, हमारी खुशी को चौगुना कर रहा होता है, वह झुग्गियों में रह रहा होता है। उसी शादी में कोई व्यक्ति जो हमें वहां के सबसे आलीशान पकवान प्रस्तुत कर रहा होता है। जो हमारी खुशियों को चार गुना कर रहा होता है, वह वहां झुग्गियों में रहता है। कौन है वह व्यक्ति! उसके बिना हमारी खुशियां, हमारी जिन्दगी चल पायेगी क्या? वहां रहने वाला व्यक्ति, हर सुबह हम में से बहुत लोगों के यहां अखबार डालते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग वहां उन झुग्गियों में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम अपने बच्चों को लेकर ऑटो में रिक्शे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो व्यक्ति बहुत सारे ऑटो वाले झुग्गियों में रहते हैं दिल्ली के। मैं खुद जिस विधान सभा क्षेत्र पटपड़ गंज का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां बहुत सारी झुग्गियां हैं। और झुग्गियों में मैं जानता हूं कि उन झुग्गियों में दिल्ली के कई अच्छे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वहां रहते हैं। सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक वहां रहते हैं जो गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झुग्गियों में रहने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वह झुग्गियों में रह रहा है, और हमारे सिस्टम की मानसिकता में बहुत दोयम दर्जे का मान लिया गया है। लेकिन मैं ये बात कहकर यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन है, वह हम से अलग कैसे है? उसका दर्जा हमसे अलग कैसे है, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह किसी भी जगह रहता हो, किसी से अलग कैसे हो सकता है? वह दोयम दर्जे का कैसे हो सकता है, वह पॉलिसी

में दोयम दर्जे का कैसे हो जाता है? मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में हम यहां बैठे हुए हैं, हमसे पहले हम दो बजे जब यहां आते हैं तो कोई व्यक्ति कोई महिला आकर इसकी झाड़ पोंछ करके जाती है। आप देखेंगे कि उन झाड़ पोंछ करने वाले, जिनकी वजह से हम यहां धूल रहित वातावरण में आकर बैठ पाते हैं, उनमें से कितने ही लोग झुग्गियों में रहते होंगे। इस सदन की लाइट फिट करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है कि झुग्गियों में रहता होगा। मैं कहना चाहता हूं कि सदन से लेकर हमारे तमाम कार्य-स्थलों तक हम बस में जायें, आटो में जायें, रिक्शा में जायें या शादी में जायें, जहां जायें इन सब के बीच में हमारी जिन्दगी का हिस्सा एकदम चेन है, चेन ऑफ्टर चेन है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। वे झुग्गी में रह रहे हैं। जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है, जब उनके लिए कोई कानून नियम बदलने की बारी आती है, तो फिर सबसे पहले जिस चीज को दरकिनार किया जाता है, वह है झुग्गी वासी। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की, ये हमारे एग्जिक्यूटिव की, या मैं कहूं कि हमारे चिन्तकों की बहुत बड़ी विडम्बना है। क्यों रह रहा है वह झुग्गी में यह भी देखिये। आज मैं दिल्ली के विकास का क्रम देखता हूं। देखता हूं कि दिल्ली में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। वहां दिल्ली विकास प्राधिकरण और तमाम ऐसी संस्थाओं ने फ्लैटस बनाने शुरू किए, कोठियों के लिए प्लाटस काटने शुरू किए। और जब फ्लैटस बनाने शुरू किए 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले। तो जो फ्लैट 20 लाख रु. का बनाया गया, कभी हमारे प्लानर्स ने ये नहीं सोचा कि उस बीस लाख के फ्लैट में जो व्यक्ति आकर रहेगा। या जो व्यक्ति उसमें रहेगा, 20 साल पहले या 25 साल पहले बीस लाख रुपये भी बहुत होते थे। अभी भी बहुत होते हैं गरीब आदमी के लिए। लेकिन मकानों की कीमत के हिसाब

से देखें तो उस वक्त बीस लाख में बड़े बड़े मकान मिलते थे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। सैकड़ों मकान बनाये गये, ये कभी नहीं सोचा कि इन मकानों में जो लोग आकर रहेंगे तो उनके साथ एक सर्विस सैक्टर भी डेवलप होगा। वहां अखबार डालने वाला भी आयेगा, वहां रिक्शे वाला भी आयेगा, वहां काम वाला भी आयेगा, वहां सब्जी वाला भी आयेगा। तमाम तरह के लोग आयेंगे, वहां पंक्चर वाला भी बैठेगा। अब आदमी कहीं अगर आकर रहेगा तो इन सब चीजों की उसे जरूरत पड़ेगी। ये जरूरत पड़ेगी तो फिर देश के किसी भी कोने में आये, उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति भी वहां रहेगा। उसमें रोजी रोटी ढूंढने वाला व्यक्ति भी वहां रहेगा। और जब वह आयेगा तो वह कहीं रहेगा तो सही। वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिन्दुस्तान के जिस भी कोने से आया हो, ये संभव नहीं है कि वह दिन भर हमें भुट्टे खिलाकर जायेगा और शाम को जाकर कश्मीर में या कन्याकुमारी में या अपने गांव में जाकर रह लेगा। रहेगा तो वह दिल्ली में ही। तो यह शहर के प्लानर्स की बहुत बड़ी गलती रही। दूरन्देशी में उनकी बहुत बड़ी कमी रही। जब उन्होंने शहर को प्लान करना शुरू किया, जब शहर को प्लान किया तो कहीं भी इस चीज को प्लान नहीं किया कि यहां इस व्यवस्था में, इस शहर के पूरे क्रम में वह पुर्जा कहां रहेगा? वह व्यक्ति कहां रहेगा? जिस व्यक्ति की औकात नहीं है कि 20 लाख का फ्लैट खरीद कर वह व्यक्ति वहां रह सके। इसलिए वह आया और सर्विस सैक्टर का हिस्सा बना। वह झुग्गियों में रहा, वह झुग्गियों में बसा। हमारे कई साथी वहां हैं, जो खुद झुग्गियों में पले बढ़े हैं। हमारी दिल्ली सरकार में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो दिल्ली की झुग्गियों में पले बढ़े हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि हमारा

एक बहुत लम्बा अवसर है काम करने का। हमारे बहुत सारे साथी, कई लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी झुग्गियों में नहीं रहा। लेकिन वहां की नारकीय जिन्दगी को मैंने देखा है। सर के ऊपर पर हमेशा चलने वाला डंडा कि कब दिल्ली सरकार, डीडीए, केन्द्र सरकार, पुलिस, नगर निगम इनकी कुछ मशीनें आएंगी, इनके कुछ लोग आएंगे और आकर हमें खदेड़ देंगे यहां से। कब उनके ऊपर डंडा चलेगा। दिन रात इस खट-राट में आदमी जीता है, उनका परिवार जीता है। उसके ऊपर से रोजी रोटी की चिन्ता, मन्दी की चिन्ता, महंगाई की चिन्ता, बच्चों की पढ़ाई की चिन्ता, सुविधाएं वहां न सीवर है, न कोई facility है। इन सबके बीच जीता है। हम लोगों ने बिजली, जब-जब राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचते थे, तब से झुग्गियों में काम करना शुरू किया था। मैं और माननीय मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल जी, दिल्ली की झुग्गियों में काम करते थे, उस वक्त वहां की नरकीय जिन्दगी से रूबरू होने का लगातार मौका मिलता रहा। वहां बिजली मीटर की लड़ाई लड़ी, राशन की लड़ाई लड़ी, बच्चों के दाखिले की लड़ाई लड़ी, वहां विकास के नाम पर हो रहे फर्जी खर्चे को Right to Information की applications डाल-डालकर उजागर किया। जिन लोगों के Vested interest थे, उन्होंने हम पर हमले किये। हमारी एक साथी बहन संतोष कोहली जो बाद में शहीद हो गई इन सब लड़ाइयों के बीच में। उसके ऊपर जान लेवा हमले किये, उस माफिया ने जो झुग्गियों के दम पर पलता है। उन झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में ये सदन और ये सरकार बहुत चिन्तित है और बहुत गम्भीरता से बहुत दर्द के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ करना पड़ेगा अपने उन बहनों भाइयों के लिए

झुग्गियों में रहते हैं, हम करेंगे। और करने की जरूरत महसूस करते हैं, इसलिए करेंगे। किसी पर एहसान करने के लिए नहीं।

मैं झुग्गियों के बारे में सरकार ने कुछ कुछ काम किए बीच-बीच में। डीडीए को जब कमाई होने लगी तो डीडीए ने कहा भाई अब तो बड़े-बड़े प्लाट और फ्लैट काटने का और बांटने का समय आ गया है। झुग्गियों के विकास के लिए कौन काम करेगा। उन्होंने वो झुग्गियों का काम दूसरे विभाग को सौंप दिया। उसको भी लगा कि अब यहां से काम नहीं चलेगा। किसी और विभाग को दे दिया। मैं उस स्थिति में नहीं जाता। लेकिन कुल मिलाके आज की तारीख में हमारे यहां एक DUSIB बोर्ड है। उस बोर्ड में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के relocation के लिए, उनके पुन:स्थापना के लिए, पुर्नवास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती रही है, कागजों में दबती रही है। यहां तक की उनके लिए बनने वाले मकान भी बनते रहे और कागजों में दबते रहे। पिछले साल वो जो DUSIB का Act है, वो झुग्गी को बड़े अच्छे से define करता है। वो पूरी definition के बाद कहता है कि it is inhabited by at least 50 households as existing on 31 मार्च, 2002 तक बसे हुए किसी भी जगह पर वहां 50 या उससे ज्यादा के हाउस होल्ड को एक झुग्गी की श्रेणी में लाता है यह एक्ट। 2002, उसके बाद से झुग्गियां, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं थोडा-बहुत दिल्ली की राजनीति पर नजर रही है। तो मैंने देखा है कि झुग्गियां उसके बाद से लगातार दिल्ली की राजनीति में एक दुधारू गाय की तरह से इस्तेमाल होती रही हैं। पार्टियां जाती। जब-जब चुनाव आते। नगर-निगम के, राज्य के, विधान सभा के, संसद के। पार्टियां वहां जाती और जाकर वहां तरह-तरह के वादे करती और फिर निकल आती। और चार वादे करके आते

उसमें से एक हल्का सा वादा घुमा फिरा के पीछे से कहीं से कोई पूरा करते और इस तरह से पूरा करते कि झुग्गी वालों को कुछ नहीं मिलता। वहां की स्थिति वहीं की वहीं रहती। बल्कि और बदतर होती रहती। उधर यह एक्ट बना 2002 का तो उसके बाद से व्यवस्थाएं चलती रही, आवाजें आती रही कि झुग्गियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया जाए। वादे होते रहे, इलैक्शन्स जीते जाते रहे और झुग्गी के लोग बार-बार भुलाए जाते रहे। फिर पिछले साल एक सरकार केन्द्र में बनी। उन्होंने भी दिल्ली में झुग्गियों को लेकर बहुत बड़े-बड़े वादे किये। उनके सात सांसद उसी पार्टी के आज दिल्ली का प्रतिनिधित्व, दिल्ली की संसद में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन वहां भी कुछ हुआ नहीं। एक साल, लगभग-लगभग एक साल उसी पार्टी की सरकार ने जिसके सात सांसद यहां हैं, यहां से है, दिल्ली के लोगों ने भेजे संसद में। उसी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी चलाई लेकिन कुछ किया नहीं। इतना जरूर हुआ कि जब बार-बार पूछा गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है तो एक Provision Act उसका नाम है। NCT of Delhi Law Special Provision Act, 2011 उसमें एक छोटा सा amendment करके कहा गया कि ये जो स्थिति है वो जो पहले 2002 की समय सीमा थी वह 1 जनवरी, 2006 की समय सीमा कर दी गई। अब वहां तो 2006 की समय सीमा कर दी, लेकिन दिल्ली के DUSIB Act में वो 2002 ही रही। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं क्योंकि करते हुए दिखाने की कोशिश ज्यादा होती है, किया नहीं जाता। किया गया होता तो झुग्गी वालों के दिन कभी के बदल गए होते। इतना बड़ा बहुमत मिला था, इतनी बड़ी पावर थी। सदन में बैठकें NCT Act का परिवर्तन किया गया संसद में बैठकें। तो साथ-साथ

आपके हाथ में था आपकी सरकार थी। कहने सुनने वाला विरोध करने वाला, आवाज उठाने वाला कहीं कोई था ही नहीं। आप DUSIB Act में भी कर देते। क्या दिक्कत थी। पर ये DUSIB Act छोड़ दिया गया। क्योंकि DUSIB Act में कर देते तो हो सकता है झुग्गी वालों का कुछ भला हो जाता तो अगली बार वोट किस मामले में मांगने जाते कि हम तुम्हारा भला कर देंगे। इस लिए जान बूझके एक खूंटा समस्याओं का वहीं गड़ा छोड़ दिया गया कि नहीं जी, हम दिखाने के लिए एक्ट को बदल दे रहे है। लेकिन चलो आपकी जिन्दगी न बदले इसलिए DUSIB Act को नहीं छेड़ रहे। नहीं तो वहीं के वहीं बदला जा सकता था। नहीं बदला गया। अध्यक्ष महोदय, वो सरकार है दिल्ली में। हम सब लोगों को सौभाग्य है कि दिल्ली वालों ने हम पर भरोसा किया जिसमें झुग्गी वालों ने हम पर भरोसा किया। हम उस भरोसे को किसी भी रूप में नहीं तोड़ना चाहते। हम कहीं भी दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहते आए हैं वो करके दिखाएंगे। इस वादे के साथ इस सदन में बैठे हुए है। तो आज मैं इस सदन के समक्ष DUSIB Act के उस provision में परिवर्तन का संशोधन का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा हूं। जिसमें 31 मार्च, 2002 की जो समय सीमा थी उसको केन्द्र के amendment के अनुसार उसके एकांगी करण करते हुए 1 जनवरी, 2006 में तबदील कर दिया गया है। उसकी जगह उसको replace कर दिया जाए। इससे सम्बन्धित विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है और मैं सदन से विनती करता हूं इस विधेयक को मंजूरी देकर दिल्ली में झुग्गियों के विकास के लिए एक नया रास्ता खोलने की इजाजत सरकार को प्रदान करे। ताकि आप सब के माध्यम से सरकार जो काम वहां करना चाहती है, उनको आगे बढ़ा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री जरनैल सिंह (तिलकनगर) : अध्यक्ष महोदय, जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है, वहां विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक सदस्य नहीं है। दो सदस्य और खासकर नेता, विपक्ष वेल में नीचे बैठे हैं चाहे वो खुद बैठे हैं और सुचारू रूप से सदन भी चल रहा है लेकिन एक सदस्य के तौर पर और हमारी पार्टी जो एक लोकतंत्र में विश्वास रखती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे नीचे बैठे हैं?

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : मैं निवेदन करता हूं विजेन्द्र गुप्ता जी से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और जिसके लिए आपको दिल्ली की जनता ने चुना है। धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वास्तविकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।

उप-मुख्यमंत्री : आपको दिखाने के लिए नहीं, मीडिया को दिखाने के लिए सही जगह पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़े होकर विजेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूं और जगदीश जी से भी वो कृपया अपनी सीट पर आ जाएं। ये कॉमेंटस नहीं नितिन जी प्लीज। विजेन्द्र जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कृपया आ जाए। श्री विजेन्द्र जी, नेता प्रतिपक्ष और जगदीश प्रधान जी मेरे आग्रह को स्वीकार करें। आइए, आइए प्लीज आइए। चलिए। नहीं महेन्द्र जी अब बस हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उपमुख्यमंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन अधिनियम 2015 को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा विधेयक का पुर:स्थापन श्री कपिल मिश्रा, विधि एवं न्याय मंत्री, दिल्ली विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन में पुर:स्थापित करने की परमीशन मांगेंगे।

विधि एवं न्याय मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विधान सभा सदस्य अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक, 2015 को सदन में introduce करने की परमीशन मांगता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

---

*पुस्तकालय में संदर्भ सं. R 15150 और R 15151 पर

अब विधि और न्याय मंत्री, विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

विधि एवं न्याय मंत्री : मैं इस विधेयक को सदन में introduce करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी विधि मंत्री बने है, एक बार करतल ध्वनि से हम सभी उनका अभिनंदन कर लें। तीसरा विधेयक- माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी, दिल्ली नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 को सदन में पुर:स्थापित करने की परमीशन मांगेंगे।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिसके प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने के लिए आपने मुझे इजाजत दी है, यह भी दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसका संबंध तमाम दिल्लीवासियों के सपने से है। आप जैसा जानते है दिल्ली की सरकार एजुकेशन पर बहुत फोकस होकर काम कर रही है और दिल्ली को नालिज हब बनाने की दिशा में बहुत मेहनत के साथ दिन रात एक करके काम कर रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि दिल्ली को या किसी भी राज्य को या किसी शहर को नालिज हब केवल नए-नए इंस्टीट्यूट बनाकर नहीं बनाया जा सकता। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूटस हैं और विशेषकर जो सरकार के इंस्टीट्यूटस हैं, सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या सरकार द्वारा संचालित हों, उनमें रिसर्च और उनकी ओटोनोमी को ध्यान में रखते हुए जब सरकार निर्णय लेती है, जितने बड़े फैसले सरकार लेती है, उसके हिसाब से नालेज हब आगे बढ़ता है। दिल्ली में बहुत सारे यूनिवर्सिटीस, बहुत सारे इंस्टीट्यूटस हैं। अगर देखें तो करीब 19 सैंट्रल यूनिवर्सिटीस हैं जिसमें से डीयू, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और इग्नू ये सब हैं। कुछ सैंट्रल इंस्टीट्यूटस

भी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूटस ऑफ फैशन टैक्नालॉजी, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेकचर, लिस्ट मेरे पास में है, हो सकता है एक दो उसमें ना हो। करीब 20 से ज्यादा एआईसीटी से अपरूवड इंस्टीट्यूटस हैं। आटोनोमस, प्राइवेटस इंस्टीट्यूटस हैं हायर एजुकेशन के लिए और इसके साथ-साथ दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीस हैं- इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली टैक्नालॉजी यूनिवर्सिटी डीटीयू, एनएलयू, ट्रिपलआईटी-दिल्ली, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी दिल्ली टैक्नीकल यूनिवर्सिटी फोर वीमन है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूटस हैं दिल्ली में, जिनमें से एनएसआईटी एक है जिसका संबंध इस विधेयक से है। ये डीयू से संचालित एक कॉलेज है और भी कुछ है, सबके नाम लिस्ट में मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं और मैं यहां सदन का समय उसमें जाया नहीं करना चाहता लेकिन क्योंकि आज जिस विधेयक को मैं प्रस्तुत करने की आपसे अनुमति मांग रहा हूं, सदन से अनुमति मांग रहा हूं वो विधेयक नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का एक प्रयास है और ये प्रयास पिछले 20 साल से लंबित है। पिछले दिनों मुझे ये इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला, वहां के एक कार्यक्रम में और छात्रों के बीच, अध्यापकों के बीच, पूरा फैकल्टीस के बीच जो एनर्जी दिखी, जो ऊर्जा मुझे वहां दिखी मुझे लगा कि दिल्ली में वो दम तो है कि एक दिन अगर ठीक से मेहनत की जाए तो दिल्ली के इंस्टीट्यूटस वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूटस बन सकते हैं और उस दिन वहां से मैंने एक सपना देखा कि क्या हम कोई ऐसा समय देख सकते हैं आने वाले समय में दिल्ली में कि दिल्ली के इंस्टीट्यूटस पूरे ओटोनोमी से काम करते हुए, पूरे विजन से काम करते हुए दुनिया के टाप 100 इंस्टीट्यूटस में शामिल हो, फिर टाप 10 इंस्टीट्यूटस में शामिल हों। वो सपना वहां से ही देखा और मेरी उसके बारे में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से, शिक्षा सचिव से,

इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से इन सबके साथ चर्चा हुई। काफी लंबी चर्चा हुई और उसी में ये निकलकर आया कि इंस्टीट्यूट की वो ऊर्जा बार-बार एक्सपलोर होना चाहती थी। पिछले 20 साल से बार-बार कोशिश की जा रही थी कि एक इंस्टीट्यूट, जो अभी इंस्टीट्यूट की सीमा में है, डीयू के कॉलेज की सीमा में रहकर काम कर रहा है, वहां रिसर्च की, वहां एग्जामीनेशन प्रोसस की, वहां वो ओटोनोमी नहीं है जो उस ऊर्जा को चाहिए। वो बार-बार चाहते थे कि किसी तरह से अगर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले तो पूरे रिसोर्सिस और पूरी एनर्जी का इस्तेमाल दिल्ली के हित में किया जाए। दिल्ली की हायर एजुकेशन को एक नई ऊचाइयों पर पहुंचाया जाए। पर पता नहीं किन कारणों से मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये भी एक रिसर्च का विषय है पर पता नहीं किन कारणों से बार-बार केबिनेट तक भी फैसला हुआ, उसके बावजूद उसको टर्न डाउन कर दिया गया। वो कभी इस सदन का मुंह देख नहीं पाया। जब मैंने इसके बारे में समझा और देखा तो मुझे लगा कि इस पर तो हमें तुरंत काम करना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी देरी न करते हुए मैंने पूरी की पूरी टीम के साथ बैठकर इस विधेयक को अंतिम रूप दिया और इसको जितनी ओटोनोमी और जितना विजन इसको धीरे-धीरे टाप 100 और टाप 10 में लाने के लिए दिया जा सकता था, अपने छोटे से अनुभव, छोटे से ज्ञान के आधार पर और उस छोटी सी टीम के आधार पर जो बहुत एनर्जटिक है, उसके आधार पर उसको रूप दिया और आज ये विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है। इस भरोसे के साथ कि बहुत ज्यादा से विधेयक जब हम पास कर देंगे तो एन.एस.आई.टी. एन.एस.यू.टी. में बदल जाएगा और फिर एन.एस.यू.टी. ना सिर्फ दिल्ली के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी टैक्नलिकल शिक्षा उपलब्ध कराएगा बल्कि रिसर्च की

बेहतरीन फैसलिटिज देगा क्योंकि सिर्फ टैकनीकल एजुकेशन उपलब्ध कराने से काम नहीं चलता अगर वर्ल्ड क्लास बनना है तो बहुत अच्छी रिसर्च की फैसलिटिज भी देनी पड़ेगी। तो इस विधेयक में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रस्तावित हैं। इसकी सीटें अभी 3400 हैं। धीरे-धीरे जब ये इॅवाल्व होगा, तब ये चार पांच साल में बढ़कर 12000 सीटें तक पहुंच जाएगी और शोध की नई दिशाएं हसमें तय होंगी। इसमें इंटरनेशल एक्सपीरियंस जोड़ने के लिए, उसको स्थान देने के लिए 20 परसेंट अतिरिक्त सीटें एनआरआईज और पीआईओज और विदेशी विद्यार्थियों के लिए होंगी। ये अतिरिक्त सीटें हैं। इसको स्टार्ट अप कैपिटल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका ये संस्थान निभाएगा। कई ऐसे कोर्सिज प्लानिंग में हैं जो अभी दिल्ली में नहीं है। पूरी दिल्ली में कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हैं। 85 परसेंट स्टूडेंटस इसका ये बड़ा पहलू है कि इससे जब ये 12000 तक पहुंचेगा, आज 3400 तक हैं तो ये विश्वस्तरीय हायर टैक्नालॉजी की सुविधा, रिसर्च की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा यहां इसमें से 12000 में से 85 परसेंट छात्र दिल्ली के होंगे, दिल्ली के छात्रों को मिलेगी। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है और इससे संबंधित विधेयक को अब मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहे,

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उपमुख्यमंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 को सदन में प्रस्तुत करता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे का टी ब्रेक है और विजेन्द्र जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि टी ब्रेक के बाद वो निश्चित रूप से अपनी सीट पर बैठे और चाय मेरे कक्ष में आकर लें।

(सदन की कार्यवाही चाय काल हेतु आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराहन 4:40 बजे पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अगर विजेन्द्र गुप्ता जी कहीं इधर उधर हैं तो सदन में आ जायें अपने साथियों के साथ। मेरी प्रार्थना हैं उनसे। अल्पकालिक चर्चा। पहले विषय था ओम प्रकाश जी का। मैं ओम प्रकाश जी से भी प्रार्थना जी कर रहा हूं। जो मैंने आदेश दिया था उसे वापिस लेता हूं। वो भी सदन में आ सकते हैं। वो आयें कार्यवाही में भाग लें। अल्पकालिक चर्चा में तीन विषय हम डेली लेते हैं। सर्वप्रथम श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपका और इस सदन का ध्यान ऐसे विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि

*पुस्तकालय में संदर्भ सं. R 15152 पर

पूरी दिल्ली के लिये एक अभिशाप की तरह बढ़ता जा रहा है। यह विषय है 'अवैध निर्माण'। अवैध निर्माण का काम पूरी दिल्ली में हर जगह तेजी से बढ़ रहा है चाहे वो अनाधिकृत कॉलोनियां हों या हमारी डीडीए की कॉलोनी हो। स्थिति यह हो गई है कि एमसीडी के अन्दर एक डिपार्टमेन्ट है जो कि उसको देखता है। लेकिन वो डिपार्टमेन्ट कोई काम करने को तैयार नहीं है या उनकी मिलीभगत से वो काम हो रहे हैं जिसके कारण हर जगह निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। जगह जगह पर छोटी छोटी गलियों के अन्दर बेसमेन्ट खोले जा रहे हैं। जिसके कारण आस पास की बिल्डिंगों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन एमसीडी के लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारी दिल्ली के अन्दर बहुत सी ऐसी जगह हैं ऐसी विधान सभायें हैं जहां पर पतली पतली गलियों के अन्दर होलसेल की मार्किट बनी हुई हैं। जैसे, सदर बाजार चांदनी चौक और जामा मस्जिद यह सारी हमारी पुरानी दिल्ली के क्षेत्र हैं, जहां पर लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। और हम देखकर हैरान हैं कि छोटी-छोटी गलियों के अन्दर बेसमेन्ट खोले जा रहे हैं और वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। क्या कारण है कि तीनों एमसीडी इन कामों को रोकने में सक्षम नहीं है। क्या यह लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी हाल फिलहाल की एक घटना बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, एक सैकिण्ड, विजेन्द्र जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो आदेश मैंने ओम प्रकाश जी के लिये दिया था, आप बुलायें वो सदन में आ जायें। हां, राजेश जी, जारी रखिये।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तम नगर में अभी एक 300 गज का बेसमेन्ट खुद रहा था जिसकी दीवार

मजदूरों के ऊपर गिर गई। मजदूर घायल हो गये वो दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। न तो उनको देखने के लिये एमसीडी का अधिकारी आया न उस जगह का काम रुका। आज भी उस जगह पर काम धड़ल्ले से चल रहा है। मैंने हर अधिकारी को फोन किया लेकिन वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे। क्या उनकी मिली भगत है? यह एमसीडी का हर जगह का रवैया है। जगह जगह पर जो अथोराइज कॉलोनी हैं, वहां पर पार्कों के अन्दर कब्जा लोगों ने कर लिया है। जिसके घर के बगल में छोटा सा पार्क है, उसने गेट निकाला और उसके अन्दर कब्जा कर लिया। एमसीडी के अधिकारी वहां जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। क्या उनकी मिलीभगत है। वहां पर दबंग लोगों ने हर जगह कब्जा किया हुआ है और तो ओर जो मेन रोडस के ऊपर लोगों के मकान हैं, उन्होंने फुटपाथ पर कब्जा करके लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। चाहे वो वहां के पार्षद हों, चाहे पुराने विद्यायक हों। उन लोगों ने भी बहुत काम किया। एमसीडी उनके साथ मिलकर इसको बढ़ावा दे रही है। अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो जाती है जब सील की हुई बिल्डिंग जिस बिल्डिंग को एमसीडी ने सील किया हुआ है, और उनके खातों में भी वो सील है और उसके बावजूद भी वो दुकानें खुल जाती हैं। उसके अन्दर आफिस बन जाते हैं और उनके रिकार्ड में वो आज भी सील हैं। जब मैंने भी उनसे मांगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर सील हुई बिल्डिंगों के रिकार्ड हमको दिये जायें। आज 15 दिन हो गये, कोई भी आदमी नहीं आया। स्थिति यह है कि हमारे यहां के कमीशनर, हमारे यहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सब छुट्टी पर हैं। एक-एक हफ्ते से छुट्टी पर हैं और धड़ल्ले से काम चल रहा है। कोई काम रोकने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हम सबको मालूम है कि नेपाल में भूकम्प आया। भूकम्प की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर हमारे बहुत से भाई लोग दुर्घटना में

घायल भी हुए और मरे भी। लेकिन यह सिलसिला अभी तक जारी है। वहां पर भूकम्प आज भी आ रहा है। 4.1, 4.7 स्केल के हिसाब से आज भी चल रहा है। दिल्ली के अन्दर भूकम्प कब आ जाये कुछ नहीं पता। क्या इस तरीके से बढ़ता हुआ यह अवैध निर्माण आगे चल कर हमारे लिये मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। जो स्थिति इस समय है और जो स्थिति आगे बनती चली जा रही है इसे रोकने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। एमसीडी वालों को बुलाकर पूछना चाहिये क्योंकि एमसीडी की मिलीभगत से ही यह सब काम हो रहे हैं। हमारे साथी सब बैठे हैं आपके क्षेत्र के अन्दर भी यह दिक्कत होगी। अल्का लाम्बा जी बैठी हैं। उनके चांदनी चौक के अन्दर तो बहुत बुरी स्थिति है। मैं जब उस क्षेत्र में गया तो वहां गली में घुसने का रास्ता नहीं है और अन्दर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इसको रुकवाने का प्रयास किया जाये और ये अभी हाल फिलहाल में आज के अखबार में जो न्यूज पढ़ी की एमसीडी अवैध निर्माण रोकने में सक्षम नहीं है। और अभी वो टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। क्या यह टैक्स वसूला जाना चाहिये? यह भी एक प्रश्नचिन्ह लगता है इसके आगे। डिजास्टर मेनेजमेन्ट की रिपोर्ट में यह कहा है कि कभी दिल्ली के अन्दर भूकम्प आ सकता है। हम सब भाइयों को मिलकर इसके लिये प्रयास करना चाहिये और जो अवैध निर्माण चल रहा है, उसको रुकवाना चाहिये। एमसीडी से पूछना चाहिये कि एमसीडी इस काम को क्यों होने दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिये इसपर लाना चाहता था कि यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और आपके जो भी क्षेत्र हैं जिनके अन्दर निर्माण

कार्य चल रहा है, उनके इंजीनियर जेई वहां जाते जरूर हैं, देखते भी हैं। सब कुछ काम होते हुए लेकिन करते कुछ नहीं। इससे जनता के अन्दर एक आक्रोश पैदा हो रहा है क्योंकि गरीब आदमी बेचारा मकान बनाता है, उसका मकान तोड़ कर चले जाते हैं। स्थिति यह है कि जो अमीर आदमी और बिल्डिर लोगों के साथ मिल कर काम कर रहे हैं उनका मकान कभी नहीं टूटता। मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस विषय पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाये। हम सब भाइयों को मिलकर अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को रोकना चाहिये और हमें रोकना पड़ेगा वरना आने वाले समय में जो डिजाइस्टर होता है उसमें हम लोगों की ही बदनामी भी होगी। अगर हम रोकने में सक्षम नहीं हुए तो। यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अल्का लाम्बा जी।

सुश्री अल्का लाम्बा : अध्यक्ष महोदय जी। में आपका धन्यवाद करती हूं। अभी राजेश ऋषि जी को मैंने चांदनी चौक के लिये बुलाया था। यह हकीकत है। चांदनी चौक की संकरी गलियां हों या जामा मस्जिद की ऐतिहासिक संकीर्ण गलियां अवैध निर्माण अपने चरम पर है। सिर्फ वाल सिटी की अगर मैं बात करूं, शाहजहांनाबाद का जो इलाका है जिसमें आसिम अहमद खान जी की विधानसभा आती है मटियामहल। इमरान हुसैन भाई की भी हमारी जो है बल्लीमारान और मेरा चांदनी चौक वाल सिटी में आप यकीन करियेगा मैंने जब इसका पूरा सर्च किया 400 से कहीं अधिक मामले अनअथोराइज्ड अवैध निर्माण के जो हैं वह कोर्ट में लंबित हैं। नगर निगम से कोर्ट 14 रिमांइडर कुछ केसिस है जिनमें 14 से 10 तक रिमांइडर निचली अदालतों ने नगर निगम से दिये कि

इस पर हमें जानकारी दीजिये। नगर निगम के अधिकारी जानकर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं निचली अदालतों में और वो जो हैं, उस निर्माण को रोकने का स्टे नहीं मिल रहा है। इसलिये अवैध निर्माण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये लोग आपको बताएंगे, जब आप अब मैं कुछ गलियों का जिक्र करती हूं। तुर्कमान गेट, कूंचा काबिला, दरिबा कालान, चांदनी चौक, मांउटेन चौक, चिपली कब्र, गली मदरसा, कला महल ऐसे हैं जहां पर हमने खुद जाकर देखा, फोटो खींची, अवैध निर्माण चरम पर है इसमें बिल्कुल मैं कहूंगी जो लैंड माफिया है, उसकी मिलीभगत है। सरकार की करोड़ों रुपये की जमीन सिर्फ नगर निगम के निकम्मेपन, भ्रष्टाचार की वजह से लैंड माफिया के हाथों में जा रही है और हम जिंदगियों से भी खेल रहे हैं। वह मंजिलें जो हैं हमारे यहां पर पुरानी इमारतें जो बिल्कुल बहुत पुरानी हो गई हैं, मेन्टेनेंस मांगती है या उनका गिर जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहूंगी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, निर्माण लगातार जारी है। मैं फिर कहूंगी हादसे की तरफ मैं इशारा कर रही हूं कि एक कुदरत की तरफ से होता है और एक मैन मेड, डिजास्टर की ओर बढ़ते हैं और एक नेचुरल डिजास्टर की बात होती है। हम नेचुरल डिजास्टर को तो मैं माफी चाहूंगी, हम नहीं रोक सकते है अगर नेपाल जैसा एक हादसा होता है जहां तक मैन मेड डिजास्टर की बात है कि नगर निगम के अवैध निर्माण लैंड माफिया के साथ मिलकर हमारे जो वहां के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये धड़ाधड़ जारी है। बहुत बार शिकायत भी की, विडियो भी भेजी, फोटो भी खींची, पर अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा example बता देती हूं। इसमें 400 यहां पर जो वाल सिटी के अंदर निर्माण चल रहे हैं। एक है जिस पर मुझे हैरानी हुई कि 2335 कटरा आलम बाग, बल्ली मारान, का ये है जहां पर धड़ाधड़ अवैध

निर्माण चल रहा है और लैड माफिया खुद कोर्ट में चला जाता है स्टे के लिये, स्टे ले आता है ये भी रास्ता आफिशियल ने उनको दिखाया है कि आप कोई भी लैड माफिया कब्जा कीजिये, निर्माण शुरू करिये और कोर्ट खुद ही चले जाइये और उस पर निर्माण के लिये स्टे ले आइये ताकि आपको नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया जायेगा सफाई के लिये और फिर नगर निगम अधिकारी आपकी मदद करेंगे, पेश नहीं होंगे और इस पर्टीकुलर प्रोपर्टी के लिये फोरटीन रिमान्डर के बाद भी दो सालों के बाद भी सब कुछ होने के बाद कोई जवाब नहीं हुआ। छोटी सी एक बात कहूंगी, अभी मेरे चांदनी चौक विधानसभा में खैबर पास है। अध्यक्ष जी, खैबर पास में लगातार अवैध निर्माण चल रहा था। पड़ौसियों ने निर्माण रुकवाने के लिये पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां आ गई, जब कि ये साफ है पुलिस अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हेल्प लाइन में रोजाना एफएम के जरिए करती है कि पुलिस वाले इस तरह से निर्माण रुकवाने या बनाने के लिये आपके पास आये तो आप इस भ्रष्टाचार लाइन में सूचना करिये लेकिन मेरे पास वीडियो है। अध्यक्ष जी, मैं सबूतों के साथ बात कर रही हूं कि अवैध निर्माण चल रहा था पुलिस वहां पर आई और यह कहा गया कि हमें बुलाया गया है। पुलिस वहां पर आती है और अवैध निर्माण नहीं रोकती जिसने शिकायत की है इस अवैध निर्माण के खिलाफ उसको बुलाया जाता है घर से बाहर और उसको एक्सपोज किया जाता है कि इसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है और वो महिलायें थी जिनके साथ एक एसआई पुलिस वाला जो बिल्कुल पुलिस की वर्दी में नहीं था, रविवार के दिन महिलाओं के साथ हाथापाई होती है। वो वीडियो मैंने फेसबुक पर भी डाला कि किस तरीके से आज भी एफएम पर कुछ चलता है, लेकिन हकीकत में जमीन पर पुलिस

भी कहीं ना कहीं माफिया, नगर निगम के अधिकारी, और पूरा नगर निगम इस अवैध निर्माण को रोक नहीं रहा। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपसे ये मांग कर रही हूं। सदन के माध्यम से कि कितनी संपत्तियों को इन्होंने पिछले साल में सील किया है, उसकी कृपया हमें एक जानकारी दें कितनी संपत्तियों को इन्होंने डि-सील किया है, वो भी हमें जानकारी दे दें। क्योंकि सीलिंग और डि-सीलिंग में भी अध्यक्ष जी बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। आपको किसी से पैसा लेना है, आप उसे डरा दीजिये। आपको सील करना है वो पैसा ले लेंगे आपसे और सील नहीं करेंगे या आपको कहेंगे आपकी संपत्ति जो डि-सील करनी है। वो हम करा देंगे उसके लिये भी पैसा ले लिया जाता है और डि-सील कर दिया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं नगर निगम से कि कितनी संपत्तियों को सील किया गया है कितनी संपत्तियों को डि-सील किया गया है और कितने केसिज लोअर अदालतों में pending हैं और क्यों नगर निगम उसमें लोअर कोर्ट में व्यक्त नहीं कर रही, क्यों जवाब नहीं दे रही और क्यों इस तरह से करोड़ों रुपये की संपत्ति हैं जो जमीनें हैं वो लैंड माफिया के हाथों में जाने में दिल्ली नगर निगम मदद कर रहा है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनरैल सिंह (तिलक नगर)।

श्री जनरैल सिंह (तिलक नगर**) :** इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिये, अवसर देने के लिये धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था जिसमें प्रधानमंत्री जी देश की जनता से बार-बार पूछ रहे थे भाईयों बहनो, पिछले एक साल से भ्रष्टाचार हुआ क्या तो

आगे से भोली भाली जनता की आवाज आती है कि नहीं हुआ। आज इस सदन के माध्यम से मैं उस भोली भाली जनता को ये बताना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री जी रोकने का दावा कर रहे हैं उसी जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जी हैं। आठ साल से एमसीडी को वहीं पार्टी दिला रही है और आज एमसीडी सबसे भ्रष्टतम निकाय बन चुका है। ये सारे दिल्लीवासी इस चीज के गवाह हैं। एमसीडी के जो जेई हैं या जो दूसरे अधिकारी है इन सब में एक अद्भुत शक्ति है, सूंघने की शक्ति है। आप मकान के बाहर 100 ईंटें और थोड़ा सा सीमेंट रख दें ये सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन जाती है। ये समझने में मैं अभी तक नाकामयाब हूं और इसमें सबसे हैरानी की बात है अध्यक्ष जी जैसे बहन अलका जी अभी पूछ रही थी कि तीन चीजें हैं जो मैं भी आपके माध्यम से एमसीडी से पूछना चाहता हूं कि पिछले आठ साल में कितनी अनअथोराइज्ड कनस्ट्रक्शन की शिकायतें एमसीडी ने रिसीव की हैं। रिसीव करने के बाद अब जैसे 100 शिकायतें आती है तो सब के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उनमें से कितनी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद फारमेलिटी के लिये कार्रवाई करके चले जाते हैं फिर से वो बिल्डिंग as it is बन जाती है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कालोनियां दिल्ली में अनोथराइज्ड कॉलोनियां बन चुकी है और कार्रवाई होने के बाद आज की डेट में उन कम्पलेंटस का वर्तमान स्थिति क्या है। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार की लत में डूबी एमसीडी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये भ्रष्टाचार से बाहर आना ही नहीं चाहती। किस तरह से एमसीडी और दिल्ली पुलिस मिलकर दिल्ली में होने वाली अनअथोराइज्ड कनस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रही है, ये सारे दिल्ली वाले जानते हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता

को एमसीडी के भ्रष्टचारी चंगुल से निकालने के लिये जरूरी है कि ऐसी पॉलिसी बने आसानी से नक्शे पास हो सकें और प्रेक्टिकल कंडीशनस को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बने ताकि जो जैसा लोग करप्शन के लिये दे रहे हैं, उनको मजबूरी में देना पड़ रहा है। आज दिल्ली में कोई ईमानदरी से भी मकान बनाना चाहता है बकायदा नक्शे ले के तो नहीं बना सकता। कुछ पॉलिसीस में हिच है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यहां तक अभी तक की चर्चा में जो विषय मेरे संज्ञान में मेरे आने के बाद में यहां सुने, उसमें नगर निगम के काम काज पर चर्चा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अनअथोराइजड कनस्ट्रक्शन।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अनअथोराइजड कनस्ट्रक्शन। जबकि हमको ये चर्चा नगर निगम के बारे में विस्तृत रूप से करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक पर्टीकूलर ईशू को चर्चा करते वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था सुनने में कि जैसे कोई दुर्भावना से, बदले भावना से या सिर्फ विरोध के लिये विरोध करने की भावना से शब्दों को इस्तेमाल हो रहा है। जब कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम इसी शहर का एक अभिन्न अंग है। अब दिल्ली नगर निगम नहीं है वो ट्राइफरकेटिड तीन हिस्सों में विभाजित उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी उत्तरी, पूर्वी नगर निगम और दक्षिणी नगर निगम। अनधिकृत निर्माण का यह जो सिलसिला है या जो समस्या है यह लगातार दिल्ली में पिछले

लगभग 60 वर्षों से निरंतर और सतत् है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में लोग बहुत बड़ी गति से आ रहे हैं, परिवार बड़े हो रहे हैं, एक वो निर्माण है जो एक छोटा-मोटा निर्माण है, परिवार के दृष्टि को, परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कोई एक बाथरूम की आवश्यकता पड़ती है, कोई एक छोटी सी रसोई की आवश्यकता पड़ती है, कोई एक बहुत ही इनोसेंट-वे में लोग गरीब स्थानों पर इकोनोमिकली वीकर सेकशन्स में उस तरह की अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवार बड़ा होने पर 20 वर्ष में परिवार का स्वरूप बदल जाता है, पुत्र की शादी हो जाती है, परिवार बड़ा हो जाता है लेकिन दिल्ली में नया स्थान खरीदने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है। अगर हम इसकी समस्याओं को ध्यान में रखकर, इस समस्या का हल हो और जो भ्रष्टाचार की बात, कोई कमर्शियल निर्माण की बात है, उस पर कैसे सख्ती हो, कैसे उसका रास्ता निकाला जाये और फिर नगर निगम की और भी जो समस्याएं हैं जिसके बारे में यहां पर सदन में टेबल होगी जिस पर चर्चा हो। आज नगर निगम बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और जिस तरह से फाइनेंस के मामले में, रिसोर्सेस के मामले में आज नगर निगम के पास धन उपलब्ध नहीं है, यह हमको समझना पड़ेगा। यह नगर निगम इस शहर का अंग है। लोगों से जुड़ी हुई रोजमर्रा की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर इस पर कोरी राजनीति करने की कोशिश की जाएगी तो दिल्ली की जनता हर बात को समझ रही है, जान रही है, देख रही है।

अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि अब ट्राइफरकेशन हुआ था कितनी तेजी से, जल्दबाजी में हुआ, राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर कांग्रेस के लोगों ने किया है। श्रीमती शीला दीक्षित जी इसके लिए सीधे तौर पर कहीं न

कहीं दोषी है। मुझे यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। उस समय के आंकड़े उस समय विश्लेषण, उस समय विशेषज्ञों ने कहा था कि आय के साधन कम है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ रही है और अगर अकेले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आय के स्रोतों को देखा जाये तो वो इतने हो ही नहीं सकते, जितने उनके खर्चे हैं, रेवेन्यू गैम है बहुत बड़ा और वो तभी पूरा होगा जब चौथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में चर्चा के लिए आयेगी, यहां पर उस पर चर्चा होगी और उसकी सिफारिशों पर सदन की मोहर लगेगी और उसके अनुसार नगर निगमों को पैसा दिया जायेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज जो सबसे महत्व का विषय है, उसके बारे में सत्तारूढ़ दल बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज भी इस सदन के समक्ष जितने भी पेपर्स आये हैं, जो भी एजेंडा आया है, जो भी इंडेक्स आया है, कहीं भी चौथे दिल्ली वित्त आयोग का जिक्र नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, कि उपमुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष इस बारे में आज जरूर वक्तव्य दें और इस चर्चा में भाग लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया और राजेश ऋषि जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने गम्भीर विषय को यहां पर उठाया। अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वो विधान सभा क्षेत्र आज के समय में एक कंक्रीट जंगल बन चुका है, वहां पर इतनी पतली-पतली गलियां हैं, सराय काले खां में इतनी पतली-पतली गलियां हैं और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार मुझे लगता है अनअथोराइज कंस्ट्रक्शन और बिल्डर माफिया। जिस तरीके से अनअथोराइज

कंस्ट्रक्शन एमसीडी के शह पर बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से सारे नियम, कायदे, कानून को ताक पर रखकर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, यह आने वाले समय में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। हम सभी लोगों ने देखा कि नेपाल में जिस तरह की त्रासदी आई और मैं कल ही डिजास्टर मैनेजमेंट के एक रिसर्चर से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर इस तरह का वाकया दिल्ली में घटित हुआ तो जिस तरह का अनअथोराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली में चल रहा है, वो बहुत ही गम्भीर स्थिति होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक सनलाइट कॉलोनी है जिसमें दो साल पहले करीब एक पांच मंजिला इमारत बनी और बिल्डर ने पांचवां फ्लोर किसी व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति ने वो फ्लोर खरीद तो लिया, उसके एक महीने बाद एमसीडी वाले उस बिल्डिंग को तोड़ने आ गये। एमसीडी वालों ने उस फ्लैट की छत तोड़ दी। छत तोड़ने के बाद जब वह बिल्डर के पास गया तो बिल्डर ने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एमसीडी से बात करो। अब वाकया यह है कि आम आदमी तो फंस गया, उसने तो फ्लैट खरीद लिया अब वो जाये या तो वो कोर्ट केस करें, कोर्ट के धक्के खाये, एमसीडी के धक्के खाये या बिल्डर के पीछे पड़े। आम आदमी तो फंस गया है। अब वो मेरे ऑफिस आता है, जब मैं ऑफिस में रहता हूं तो मेरे ऑफिस में आता है कि आप बताइये, अब मैं क्या करूं? मेरे पास भी उसको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। ये सारा वाकया जो है एमसीडी के तले हो रहा है और इसी तरह का एक ही वाकया नहीं है। इसी तरह के ढेर सारे वाकये हैं जिसमें कि आम आदमी पिसता जा रहा है इन अनअथोराइज कंस्ट्रक्शन में।

अध्यक्ष महोदय, एक और इंसिडेंट है, जिसमें कि सारे नियम, कायदे, कानून ताक पर रख दिये गये। एक बिल्डिंग बन गई थी हमारे क्षेत्र में, वो बिल्डिंग किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से या नींव मजबूत न होने की वजह से एक तरफ झुक गई तो उस बिल्डिंग को एक तरफ से जैक्स पर खड़ा कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसकी जब कंप्लेंट करी एमसीडी में तो उस बिल्डिंग को तुड़वाने और सील करवाने की बजाय उस जैक्स को हटाकर वहां पर दोबारा पिलर खड़े कर दिये गये और उस बिल्डिंग को दोबारा बनवा दिया गया। यह बहुत शर्मनाक चीज है अगर नेपाल जैसी त्रासदी हमारे दिल्ली में हुई तो उस बिल्डिंग का क्या होगा, यह सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारे जंगपुरा क्षेत्र में पिछले कई सालों से अनअथोराइज कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से चल रहा था इसमें वहां के पुराने नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था जिसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बिल्डर लॉबी में शामिल किया जिसके कारण जंगपुरा क्षेत्र आज एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है वहां पर इतनी संकीर्ण गलियां हैं, जहां पर गुजरना भी डरावना लगता है। एक स्ट्रीट लाइट तक लगाना वहां पर सम्भव नहीं है क्योंकि गलियों में इतना स्पेस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जिस तरह से जरनैल भाई ने रिपोर्ट मांगी। उस तरीके से एमसीडी से मैं रिपोर्ट यहां पर आपके माध्यम से मांगना चाहता हूं कि जितनी बिल्डिंग सील हुई हैं और जितने हमारे दिल्ली क्षेत्र में अनअथोराइज बिल्डिंग्स हैं, उनका डिटेल दें current मापदंड के according. एक और बहुत अहम चीज है कि जब तक यह बिल्डर माफिया राज करता रहेगा और कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो कि unregistered है और जिनके पास एक कोई प्रोफेशन नहीं है। वो अपने समझ के according बिल्डिंग बनाते रहते हैं। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं उसका

एक वाकया शेयर करता हूं। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं उस बिल्डिंग की गुणवत्ता ही इस तरीके की, उस बिल्डिंग में मैं किराये पर रहता हूं, उस बिल्डिंग की हालत ही ऐसी है जबकि वो सिर्फ दो साल पहले ही बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग में दरारें पड़ने लग गई हैं तो जो मैटिरियल यूज किया जा रहा है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में वो भी बहुत अहम चीज है कि जिस तरह की मैटिरियल यूज हो रहा है उस बिल्डिंग में उसकी गुणवत्ता चैक कराई जाए ताकि आने वाले हादसों से दिल्ली को हम महफूज रख सकें, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह कालकाजी।

सरदार अवतार सिंह : अध्यक्ष महोदय जी, अभी बात हो रही है दिल्ली में अनओथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि हम बदले की भावना से बात कर रहे हैं पर आज दिल्ली की सारी जनता जानती है कि जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई अपना घर बनाना चाहता है, बिल्डर की तो बात अलग है, कोई घर बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको किस-किस रास्ते से गुजरना पड़ता है कितनी मुश्किलें आती है ये वही लोग बता सकते हैं क्योंकि रात में भी मेरे घर में, क्योंकि मैं मीटिंग में था तो कुछ लोग आये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं, दीवान चंद जी। तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा है दो मिनट रुको, वो बाहर ही खड़े रहे गर्मी में, उनके घर की समस्या थी, अपने घर में रह रहे हैं वो। उन्होंने बताया कि एमसीडी वाले आये हैं और उनके घर की ऊपर की छत तोड़ दी है, बीच में रह रहे हैं वो एक फ्लोर को तोड़ गये साथ में दो फ्लोर को और तोड़ गये हैं। ये बड़ी समस्या है आप कह रहे हैं बदले की भावना से बात कर रहे हैं। मेरी समझ में

नहीं आ रहा है कि आप क्यों अपनी आंख में पर्दा डाल रहे हैं। क्या हमारे लोगों को दिल्ली वासियों को पता नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, एमसीडी क्या कर रही है। आप उसको इतने बड़े आराम से कह रहे हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बदले की भावना हो रही है लोगों से जाके उनसे उनका हाल पूछो कि कैसे वो किस तरीके से रह रहे हैं हमारी गोविंद पुरी में कई सालों से, हमारा जन्म भी वहां पर हुआ है, हम देख रहे हैं, कम से कम तीन-चार हादसे हो चुके हैं जब कोई आंधी भी आती है बिल्डिंग गिरती है चार इंची की दीवार बनाते हैं और 6-6 मंजिल ले गये हैं ओथराईज। एलाउ हमको तीन मंजिल है, ज्यादा से ज्यादा चार मंजिल कर लेते हैं तो उसकी जो दो-दो मंजिल हैं उसकी अगर इंक्वाइरी करवाई जाये उनकी उनके जेई से पूछा जाये उस वक्त जो ड्यूटी पर थे अफसर उनको चैक किया जाये, मैं कहूं तो एमसीडी में गुंडा राज चल रहा है बिल्कुल। उनके जेई को जब हम बुलाते हैं हमको बात करो। इनकी बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हो तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, और मिलकर कह नहीं रहे पर भ्रष्टाचार तो खुली किताब है कि पैसा लेके काम हो रहा है और एक-एक बिल्डिंग के ऊपर छत के ऊपर कम से कम 70-80 हजार रुपया एक-एक लाख रुपया, ऐसे ले रहे हैं आप कह रहे हैं आप क्यों ऐसे बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है मानते हैं कि एमसीडी दिल्ली को चलाने वाली है, सफाई काम उनको करना है आप एमसीडी के काम देखिये, क्या मोदी जी को पता नहीं दिल्ली में रह रहे हैं, सैंट्रल गवर्नमैन्ट यहां पर है, उनको पता नहीं है, ध्यान नहीं है, यहां पर सफाई की जरूरत है, जगह-जगह कूड़ा फैंका हुआ है। क्यों नहीं कहते वो एमसीडी को?

दिल्ली एक कैपिटल है, राजधानी है यहां की। उनका फर्ज बनता है कि इसको देखें और इसके ऊपर अपना विचार करें। एमसीडी से अपनी मिटिंग करें और बोलें कि दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाये। यहां पर लोगों ने बाहर से आना है। बाहर से जब लोग आते हैं तो उनके मन पर क्या असर जाता है, ये हमारे देश की बात है, हम सब भारतीय हैं। उस निगाह से देखो आप। आप कह रहे हैं हम बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आम आदमी ने समर्थन दिया है हमें और उसके लिये हम तत्पर हैं। पर क्या करें? जब एमसीडी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं।

अगर सफाई के मामले में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि हमारी गली में जब हम एमएलएज ने पीछे जब सफाई का अभियान चलाया, उस वक्त एमसीडी वाले जब हमने काम शुरू किया, झाड़ू लगाना शुरू किया उस वक्त एमसीडी वालों ने गलियों में झाड़ू लगाना शुरू किया। नहीं तो अदरवाईज पहले कभी सफाई ही नहीं हुई। आप बात कर रहे हैं पर्दा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : अवतार सिंह जी थोड़ा संक्षेप कीजिए प्लीज।

सरदार अवतार सिंह : सर मैं चाहता हूं जो भी बिल्डिंग बन रही हैं, उनको चैक किया जाये उनके ऊपर रोक लगाई जाये जो 6-6 मंजिला बिल्डिंग बन रही हैं उनमें अनओथराईज कन्कशन लगे हुए हैं पानी फालतू यूज कर रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम को ठीक किया जाये, एमसीडी वालों को बोला जाये कि वो तरीके से नक्शा पास करके, जो भी है सिस्टम से, नक्शा पास करवायें, नहीं तो जो हम नेपाल की बात कर रहे हैं हमारे यहां भारत में भी हुआ है। जो अनओथराईज बिल्डिंग बनती हैं, उनको रोकना चाहिए। लोगों की

भलाई के लिए करना चाहिए मैं यही कहना चाहता हूं, जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा में बिजली पानी पर श्री ओम प्रकाश शर्मा जी अपना विषय रखेंगे,

श्री ओम प्रकाश शर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं केवल आप से आधा सेकेण्ड का समय चाहता हूं। जो आम पार्टी की सरकार, आम आदमी और आम पार्टी की सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प करते हुए दिल्ली में आयी और दिल्ली की जनता ने भरपूर मात्रा में आपको समर्थन दिया तो भ्रष्टाचार से लड़ने का जो आपका संकल्प है। मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोधी पार्टी का सदस्य होते हुए, मैं इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। आज जो पूरा सदन है, मैं पिछले 46 साल से अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन से जो हम काम कर रहे हैं। हम लोग एक सपना देखते थे कि हम विधान सभा, कारपोरेशन या किसी सदन के सदस्य बनेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में हमारा योगदान होगा। आज ईश्वर की कृपा से ऐसा समय आ गया है। हम सब लोग जितने भी माननीय, सम्माननीय सदस्य यहां बैठें हैं। इस गरिमामयी सदन के हम सदस्य हैं और लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्रीमान सीएम साहब यहां उपस्थित नहीं हैं मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है। जिस तरह अखबारों में तरह-तरह की बात आ रही है हम सभी के सभी जो 70 सदस्य हैं। तीन महीना या जो भी समय सीमा हो उसमें सबकी डिग्रियों की जांच कराकर **...व्यवधान।**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, विषय बिजली-पानी के लिए आपकी चर्चा का था। ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिये एक बार।**...व्यवधान**। ये ठीक नहीं है। एक सेकेण्ड जगदीप जी**...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, मुझे एक सेकेण्ड का आप मौका देंगे।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। नहीं प्लीज। मेरा ये कहना है। नहीं, जगदीप जी आप बैठिये प्लीज। मेरा ये कहना है कि ये रूल 55 के अन्तर्गत, नियम 55 के अन्तर्गत अल्पकालिक चर्चा है। उसमें आपका नोटिस प्राप्त हुआ। बिजली-पानी। नितिन जी, व्यवधान। सदन का समय दिल्ली की। आपने बहुत अच्छी शुरूआत की और बिजली पानी पर दिल्ली की जनता की समस्या को आप रखें सीधे तरीके से ताकि और सदस्य अल्पकालिक चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो एक सेकेण्ड लेना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो।**...व्यवधान**। सेन्टेन्स पूरा हो जाये। मैं अपना सेन्टेन्स पूरा करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये विषय आप कई बार कह चुके हैं। सुबह भी कह चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं केवल सेन्टेन्स पूरा करना चाहता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये जो सम्माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं और अखबारों में जो ये चीजें आ रही हैं। मैं जब सुबह उठता हूं, अपने घर में झाड़ू लगाता हूं, पड़ोसियों के घर में झाड़ू लगाने नहीं जाता। दूसरे सदन के लोग दूसरे सदन की बात करें। मैं इस सदन का मेम्बर हूं। इसलिए इस सदन की बात कर रहा हूं। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि एक समय सीमा में सभी की

डिग्रियों की जांच करायी जाए। धन्यवाद। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चलिये कोई नहीं। कह लेने दीजिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, चलिये, अगर आप भ्रष्टाचार के प्रति **...(व्यवधान)** नहीं हैं तो निकलवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मदन जी, मदन जी। इनको समय सीमा का ध्यान रखना है। उनको बोलना है आपका विषय है समय नहीं मिलेगा। नहीं ओम प्रकाश जी नहीं आप बिजली पानी पर आइये**...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दिल्ली के चुनाव में आम पार्टी बिजली हाफ और पानी माफ। आम पार्टी बिजली हाफ और पानी माफ के स्लोगन के साथ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि। थोड़ा शान्त हो जाइये उनको बोलने दीजिये जो बोल रहे हैं प्लीज। हमारा समय खराब हो रहा है हमको इस विषय पर चर्चा करनी है। समय कम है**...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बिजली हाफ और पानी माफ**...(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये जो आप बहुत खुश हो रहे हो न। ये डिग्री वालों को ध्यान करो। ये सवाल ये सब बहुत खुश हो रहे हो न। सब अन्दर जाने वाले हैं। दिल्ली में। अरे भईया पूरे हिन्दुस्तान की कराओ पहले अपनी कराओ। पहले अपनी 70 के 70 लोगों की डिग्री चेक होनी चाहिए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, प्लीज। मदन जी, मदन जी। अब कोई सदस्य नहीं बोलेगा। उनको पांच मिनट में अपना विषय पूरा करने दीजिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत और उसके बावजूद सरकार का असंवेदनशील रवैया। दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार इस पर चेतती नजर नहीं आ रही है। इसके उलट दिल्ली सरकार व इसके मंत्री दिन प्रतिदिन किसी बड़े भ्रष्टाचार या अन्य किसी असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाये जा रहे हैं**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चलो उनको बोल लेने दीजिये, जो वो बोल रहे हैं। हां बोलिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दिल्ली सरकार आये दिन किसी न किसी वजह से कभी केन्द्र सरकार से कभी दिल्ली पुलिस के साथ उलझती नजर आ रही है

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये बिजली पानी का विषय है क्या। ओम प्रकाश जी, ये ठीक नहीं है। विजेन्द्र जी। मेरा आग्रह है, ये ठीक नहीं है। नहीं। सदन का समय खराब कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। मुझे बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कितनी बार सेन्सर करोगे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं सेन्सर नहीं कर रहा हूं। बिजली पानी पर, चलिये कहिये आप क्या कहना चाह रहे हैं। कह लीजिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अब जब कि फिर से दिल्ली की जनता से लोक लुभावने वायदे जैसे कि पानी माफ, बिजली हाफ, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इत्यादि लेकिन इसके इतर न तो दिल्ली में बिजली की समस्या पर कोई ध्यान दिया है और न ही पानी की कमी से तरसती दिल्ली के लिए कोई ऐसी योजना दे सकी जिससे कि दिल्ली की जनता को इन दोनों समस्याओं से कोई छुटकारा मिल सके। इसके विपरीत दिल्ली में बिजली की कटौती बढ़ गयी है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। आठ से दस घण्टे बिजली कटौती आम बात हो गयी। यह स्थिति तब है जब कि केजरीवाल जी बिजली कम्पनियों पर जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद बिजली कम्पनी पर इसका कोई असर होता दिखायी नहीं दे रहा है बल्कि बिजली कम्पनी उनको ठेंगा दिखाकर उसका उपहास उड़ा रही हैं और दिल्ली के अन्दर 4 से 6 परसेन्ट बिजली दामों में ताजी ताजी बढ़ोत्तरी करने की कार्रवाई चल रही है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब सरकार दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ौत्तरी करने का मन बना रही है।**...व्यवधान**। सुनिये जरा ध्यान से। 51 प्रतिशत के मालिक आप है। आप उससे बच नहीं सकते। दिल्ली की जो सरकार है। दिल्ली सरकार, दिल्ली की सरकार दिल्ली की बिजली कम्पनियों में पार्टनर है। व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दीजियेगा। आपका समय आयेगा तो आप नोट करिये। आप नोट करिये क्या बोल रहे हैं**...(व्यवधान)**। आप इधर ध्यान देकर बोलिये। आप इधर देखकर बोलिये। नहीं उधर छोड़िये। आप बोलिये। आप जल्दी समाप्त करिये प्लीज। भाई मेरी प्रार्थना है। भाई राजेश जी...व्यवधान। मैं बोल रहा हूं। नहीं एक सेकेण्ड। भाई राजेश जी, मैं एक बात कह रहा हूं ये

उचित नहीं है...**(व्यवधान)**। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। ये टोका टाकी बन्द करें प्लीज जरा। व्यवधान। वो जो गलत तथ्य दे रहे है, उनको नोट करिये। भाग लीजिये चर्चा में। मेरी प्रार्थना है शान्त रहिये प्लीज। चलिये प्रकाश जी। आप इधर देखिये, बोलिये। आप जल्दी करिये। भाई कोई नहीं बोलेगा। मेरी प्रार्थना है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने (पीपीएसी) पावर परचेज एडजेस्टमेन्ट कॉस्ट को बहाल कर दिया है जिसके तहत टाटा पावर इलाके में चार प्रतिशत, एनडीएमसी इलाके में पांच प्रतिशत और बीएसईएस यमुना और राजधानी के इलाके में 6 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है। पीपीएससी जुलाई, 2014 से मार्च, 2015 के बीच के लिए लागू होगा। इसके उपरान्त दिल्ली सरकार में 1 जुलाई, 2015 से फिर बिजली के दामों में भारी बढ़ोत्तरी करने जा रही है। यह तर्कसंगत नहीं है। आप आदमी पार्टी की ओर से निजी कम्पनियों के खाते की जांच सीएजी से करवाने के लिए, उनके लाईसेन्स रद्द करने के लिए, उनके ऊपर एफ.आई.आर. लिखवाने के लिए 49 दिन की सरकार में आपने बड़े-बड़े वायदे किये थे। आज उसके उपरान्त यमुना में बहुत पानी बह चुका है। कृपया बताये आपने इस अन्तराल में इस विषय में क्या किया। न तो बिजली कम्पनियों के खातों की जांच हुई और न ही दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की बिजली कम्पनियों पर कोई अंकुश लगाया गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में बिजली के दामों में भारी बढ़ोत्तरी के बाद भी दिल्ली में आम आदमी की सरकार मूकदर्शक बनकर रह गयी। कमोबेश यही हाल दिल्ली में पीने के पानी का भी है। राजधानी में एक ओर तो गरमी में पारा बढ़ता जा रहा है, लोगों के पसीने छुड़ा रहा है दूसरी ओर

पानी की किल्लत लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। दिल्ली में पीने का पानी मिल नहीं रहा है और जो भी मिल रहा है वो इतना दूषित है कि उसे पीकर अभी हम लोग रंगपुरी के एक वृद्ध आश्रम में हम तीनों बीजेपी के सदस्य गये थे। मीडिया ने भी काफी उसको लिया है। पानी नहीं मिल रहा है दूषित पानी मिलने से दो महीने में वृद्ध आश्रम की चालीस लोगों की मौत हो गयी। ये दिल्ली सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप इधर देखिये। आप इधर देखके बात करिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ठीक है, अध्यक्ष जी। एक ओर दिल्ली में पीने के पानी की कमी है, जितने भी हैं, वे दूषित हैं। यह पानी बिल्कुल पीने के योग्य नहीं है। ऊपर से जल बोर्ड के जो भी टैंकर पानी की आपूर्ति के लिए पहुंचते हैं, उन पर पानी माफियाओं की गुंडागर्दी ने दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। जल बोर्ड के जो टैंकर पीने के पानी की सप्लाई के लिए कॉलोनियों में आते हैं, उन पर सरकार के शह पर माफिया अपना हक समझ लेते हैं और ये टैंकर वहीं खड़े होते हैं जहां सरकार के विधायक व आम पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। इस प्रकार अन्य लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार आम जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इसी प्रकार बिजली से सम्बन्धित एक बात मुझे और आपके संज्ञान में लानी है। एक दिल्ली बीएसईएस में जेई डालचन्द कपिल जिनका नम्बर है 31475, जिनको कि डिसमिस कर दिया गया 22.03.2004 को। अब उनको जो रिवार्ड दिया गया है बिजली कम्पनियों के द्वारा reward of corruption of corrupt employee

by BSES, Rajdhani Power Ltd. promoted him as Dy. General Manager और उसके मकान के किराये और दूसरी चीज हैं उन्हें असंवैधानिक रूप से 35 हजार 35 लाख 45 हजार पांच सौ चालीस रुपये जो उसको माफ कर दिये गये है जो कि जनता की...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर दीजियेगा न। ओम प्रकाश जी, आप बोलिये। जल्दी बोलिये प्लीज। ओम प्रकाश जी, आप इधर देखके बात करना।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये बीच-बीच में जो टोक रहे हैं। ये जो पब्लिक के खून और पसीने की कमाई है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये जो पब्लिक के खून और पसीने की जो कमाई है जिसमें दिल्ली की सरकार पार्टनर है ऐसे ही राजधानी पावर इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इस विषय में एक बात और आपको कहना चाहता हूं ये जो सस्पेंडेड व्यक्ति है, ये एक यूनियन चला रहा है जिसके सरपरस्त जिसके पैटर्न हमारे एक्स कानून मंत्री श्रीमान भारती जी है जिसका यह पोस्टर मेरे हाथ में है तो इस प्रकार लोगों का शह देना पब्लिक फण्ड दुरुपयोग करना और उसका भार जनता के ऊपर पड़ना। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं इसकी गहन जांच हो। अरे ये तो इल्जाम है। तो मैं कौन सा जेल भेज रहा हूं आपको?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिय ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आप इधर बात करिए ना। राखी जी प्लीज। हो गया पूरा हो गया चलिए धन्यवाद। चलिए सोमनाथ भारती जी। एक सेकेण्ड राखी जी श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। शुरूआत में सबसे पहले बीजेपी के माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा इन्होंने जिस अदब से बात रखी एक तो कहीं से लिख के लाये थे और किसी ने डिक्टेट किया इनको ये...

अध्यक्ष महोदय : भाई आप मत बोलिए। ध्यान से सुनिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : बीएसइएस के अन्दर एक बहुत बड़ा स्केम चल रहा है आउटसोर्स के जो एम्पलाइज है अभी पिछले दिनों तीन एम्पलाइज ने दो की तो इलैक्ट्रोक्यूश्न से करेन्ट लगने से मौत हुई और एक ने आत्महत्या कर ली! अच्छा होता अगर ओम प्रकाश जी इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालते। करीब करीब आठ हजार एम्पलाइज ऐसे है जो कि आउटसोर्स के है। दलाली का धन्धा चल रहा है बीच में दलाल नियुक्त किये गये है क्योंकि उसको अभी हम इन्वेस्टीगेट करेंगे। भाई आप थोड़ा बख्शिए।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, आप थोड़ा शांति से सुनिए।

श्री सोमनाथ भारती : आप थोड़ा बख्शिये, इसको में माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर आया हूं। हो क्या रहा है कि मैनेजमेन्ट के ही दलाल के लोग ही बीच के बिचौलिए बने बैठे है और बीस हजार तनख्वाह लेते है बीएसइएस से और आगे पास ऑन करते है आठ नौ हजार रुपये। ये शर्म की बात है। ना उनको टूल दिया है ना ही कोई सेफटी का इक्यूपमेन्टस दिया है और ये जो डीसी कपिल के बारे में बात कर रहे हैं ये दिल्ली विद्युत बोर्ड यूनियन का जनरल सक्रेटरी है और यह सीक्रेट भी था। मिस्टर डीसी कपिल

सेक्रेटरी थे जब दिल्ली विद्युत बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन हुआ। ये चूंकि डीसी कपिल उन बेचारों की जो कि आठ हजार, सात हजार रुपये में अपना जीवन यापन करते हैं और बीच में बिचौलिए मोटा माल खाकर के पता नहीं किसे पहुंचाते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहां पहुंच रहा है वह पैसा? एक जो कि अनरजिस्टर्ड यूनियन है जिसके कर्त्ता धर्ता मिस्टर कुलदीप है शायद ये ओम प्रकाश जी उनका फेवर करना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जहां जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां जहां अन्याय होगा, वहां वहां मैं भी खड़ा रहूंगा और मेरे सारे साथी खड़े रहेंगे। अगर इनको लग रहा है अभी आपकी और पोल खोलता हूं पोल खोलने दीजिए मुझे थोड़ा भरोसा रखिए मेरे पास और पिटारा है ये आपके माध्यम से सदन के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर कि इसकी जांच हो और मालूम किया जाये कि भाई, जो बीस हजार के बदले सात हजार दिया जा रहा है तो बाकी पैसा कहां जा रहा है? ये तो इनकी एक पोल खोल हुई और जो इन्होंने शुरूआत में कहा कि फेक डिग्री, ये फेक डिग्री बनता कहां है? यह फैक्टरी शुरू कब हुई? मैं तो आपके माध्यम से चूंकि भाजपा के माननीय सदस्य मौजूद है...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप बिजली पर रखिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : मैं आ रहा हूं उसी पर। चूंकि ये पूरा का पूरा ध न्धा चल रहा है, पूरे देश में फेक डिग्री का धन्धा बहुत जोर शोर से चल रहा है और अगर आज सांसदों की डिग्री की जांच हो तो कई मंत्री और बड़े-बड़े मंत्री आज नग्न हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, सोमनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)...

श्री सोमनाथ भारती : दूसरी बड़ी बात। बैठ जाइए आप आराम से।

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप सुन लीजिए बैठिए जरा। आप बैठिए तो सही। भाई साहब वो ही तो बोल रहे है।

श्री सोमनाथ भारती : बढ़िया करेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कौन कौन आदमी उसमें फंस रहे हैं अभी तो ललित आसन से परेशान है। अभी जो ललित आसन चला है देश में उसमें आपके गुरू अरूण जेटली जी फंस रहे है उसमें**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप डायरेक्ट बात ना करें प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : जी। माननीय अध्यक्ष महोदय यह चूंकि**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, संक्षेप में कीजिए कई लोगों को बोलना है।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने जो मुद्दा रखा है, उस पर मैं आ रहा हूं। अनोथराइज्ड कॉलोनियों पर मैंने बोलना था।

अध्यक्ष महोदय : भाई, वो विषय बाद में आयेगा प्लीज। वो आयेगा विषय अभी प्लीज बैठिए बैठिए। चलिए राजेन्द्र गौतम जी।

श्री सोमनाथ भारती : इन्होंने इल्जाम लगाया कि मैं इनका पैटर्न हूं इनको बड़ी तकलीफ है जिस दिन से मैंने इस यूनियन का साथ देना शुरू किया है। सारे भ्रष्टाचारी जिनका पेट इस भ्रष्टाचार से चलता है सब दुखी और इसलिए सदन के माध्यम से इनको बता दूं कि बहुत जल्दी वो सारे नाम और इनको बड़े करीब रिश्तों के नाम भी आयेंगे और अब आयेंगे तो शर्म से मुंह छिपाते फिरेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र गौतम जी।

श्री राजेन्द्र गौतम : धन्यवाद, अध्यक्ष जी आपने मुझे आज बिजली और पानी के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं अपनी बात रखने से पहले अपने साथी कपिल मिश्रा जी को बधाई दूंगा कानून मिनिस्टर बनने पर तत्पश्चात अपनी बात शुरू करता हूं। हमारी सरकार को पहले मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि हमारी सरकार ने बिजली कंपनियों को इस बात के लिए प्रेसराइज किया कि बिना किसी जायज वजह बिजली को काटा ना जाए और अगर एक घंटे से ज्यादा बिजली कटे तो उसमें पेनेल्टी लगेगी जो पिछले सालों में कभी देखने में नहीं आयी। तो मैं अपनी सरकार को इसके लिए बधाई दूंगा। साथ ही साथ मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि अभी पीछे एक साल तक एलजी के माध्यम से हमारी केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में शासन किया।

इस एक साल में जो 2013-14 का बजट माननीय अरूण जेटली जी ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रखा उसमें लगभग 750 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों को और पानी की कम्पनी को दिया जिसमें 200 करोड़ रुपया पावर रिफार्मस

के लिए और 500 करोड़ रुपया वाटर रिफार्मस के लिए दिल्ली को दिया ताकि ये वास्तव में विश्व का एक सबसे सुंदर शहर बन सके। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब से दिल्ली सरकार बनी है, इस बजट में माननीय जेतली जी ने इस बार दिल्ली को उसी तरह पहले की तरह अपना विशाल हृदय दिखाते हुए पहले की तरह बजट में इसी तरह की फाइनेंस की मदद क्यों नहीं की? इससे साफ जाहिर होता है वो इसलिए नहीं कि क्योंकि केन्द्रीय सरकार दिल्ली के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाए हुए है। किसी भी प्रकार का सहयोग हमें न केन्द्रीय सरकार से देखने को मिल रहा है और न अपने तीन जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, उनसे मिल रहा है। हर मुद्दे पर सहयोग पूर्ण रवैया अपनाने के बजाय, सही बात पर सहयोग पूर्ण रवैया अपनाने के बजाय, सही बात की तारीफ करने के बजाय सदन का समय बार-बार बर्बाद किया जाता है। ये बड़ा ही खेद का विषय है। अध्यक्ष जी, पीछे 55 परसेंट थैफ्ट बिजली में था और वो थैफ्ट काफी कोशिशों के बाद घटकर 15 परसेंट पर आ गया। तो 40 परसेंट को तो वो मुनाफा हुआ और जो घाटे की बात की गई थी पहले, उसके एवज में दिल्ली सरकार ने 1500 करोड़ रुपया इन बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर दिया। लेकिन इतने सारे पैसे के बाद भी और बिजली की चोरी इतने बड़े पैमाने पर कम करने के बाद भी कितना मुनाफा होना चाहिए था जिसका सीधा सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। ये बहुत ही शेमफुल है। ऐसा लगता है कि हमारी बिजली वितरण कंपनियां और रख रखाव करने वाली कंपनियां दिल्ली की सरकार के प्रति लायल नहीं है बल्कि उन केन्द्रीय सरकार के प्रति लायल हैं जिनको उन्होंने इलैक्शन में बहुत बड़ा चंदा दिया। आज भी दिल्ली में चुनी हुई सरकार के होने

के बावजूद वो कंपनियां दिल्ली की जनता के दुख को अपना दुख समझकर उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : गौतम जी शार्ट करिए, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की इन बिजली कंपनियों को जो ये घाटा दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। एकचुअल में ये कंपनियां घाटे में नहीं है, बहुत फायदे में हैं। इसीलिए मैं तो धन्यवाद करूंगा अपनी सरकार का कि उन्होंने इनका आडिट कराने का फैसला किया। लेकिन दुख की बात है जो पीछे एक साल में एलजी के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो दिल्ली में शासन किया गया उस शासन के दौरान इन आडिट कंपनियों को, आडिट डिपार्टमेंट को इन बिजली कंपनियों के द्वारा मदद नहीं की गई और उस पर केन्द्रीय सरकार मूकदर्शक बनी रही। अगर उस वक्त मदद की जाती तो मैं समझता हूं कि अब तक आडिट पूरा हो जाता और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सब को पता चल जाता कि दिल्ली की वितरण कंपनियां, रख रखाव कंपनियां फायदे में हैं और इसका फायदा दिल्ली की जनता को मिलता और ये रेट बिजली के अब तक कम हो जाते। यही बात मैं रखते हुए बाकी क्योंकि आपने कहा कम समय लीजिए, बोलने को तो मेरे पास काफी मैटर था लेकिन....

अध्यक्ष महोदय : अभी कई सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश ऋषि जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं ओम प्रकाश जी ऐसे नहीं। ओम प्रकाश जी देखिए मेरी बात सुनिये, नहीं कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं। अभी बाद में आप बात करें। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अभी आप बैठ जाइये। ये अल्पकालिक चर्चा एक बार पूर्ण होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अगर वे नहीं है तो उनका जवाब कौन देगा?

अध्यक्ष महोदय : आ जायेंगे अभी जवाब देने।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप उन्हें बुलाइये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है बुलवा लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बिजली और फाइनेंस मंत्री दोनों होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। ठीक है।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ओम प्रकाश जी ने अभी बताया कि दिल्ली के अंदर बिजली हाफ पानी माफ इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए सीएम साहब का। इनकी ओर से मैं ही दे देता हूं धन्यवाद। अपने उप-मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इसे बड़ी कड़ाई से लागू किया और जनता को इससे

बहुत फायदा हुआ। ओम प्रकाश जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीईआरसी जो आपके केन्द्र के इशारे पर काम करती है, उसने दिल्ली के अंदर एक लूट का काम शुरू किया था। ये लूट तब हुई जब इन्होंने 2012 में एक रिजोलूशन पास किया, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ। वो लागू तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल जी की 49 डेज की सरकार हटी और उसके बाद जब आपकी सरकार चला रहे थे एलजी साहब, तब इसको लागू किया गया। इसके माध्यम से एमडीआई के द्वारा हर इंसान को लूटा गया जो दिल्ली के अंदर बिजली यूज कर रहा था। किस तरीके से लूटा गया आप खुद जानते हैं कि अगर किसी का भी एमडीआई साल में तीन बार अगर वो बढ़ जाता है जैसे आपने 2 किलोवाट का कनैक्शन लिया हुआ है और वो आप तीन साल में अगर तीन बार आप तीन किलोवाट, ढाई किलोवाट या दो किलोवाट से ऊपर यूज कर लेते हैं तो आपका वाटेज बढ़ा दिया जाता है। जिसके माध्यम से दोनों कंपनियां जितनी कंपनियां यहां काम कर रही हैं, डीईआरसी के माध्यम से इन्होंने आम कंज्यूमर को लूटा है और लूटा हुआ धन कहीं भी प्रयोग में नहीं लाया गया। जबकि उनको जिस तरीके से किलोवाट बढ़ाये थे उस किलोवाट बढ़ाने के साथ उन्हें तारें चेंज करनी चाहिए थी, ट्रांसफारमर नये लगाये जाने चाहिए थे। जिसका उन्होंने कहीं भी प्रयोग नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इसकी जो पैसा उन्होंने कलेक्ट किया इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा गया तो गया कहां। एक चीज और बताना चाहता हूं ओम प्रकाश जी कि डीईआरसी जो आपके इशारे पर चलती है आपकी केन्द्र के इशारे पर। वो ही रेट बढ़ाने जा रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी उनको बोलने दो न। उनको बोलने दो न थोड़ा प्लीज।...धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी संक्षेप में।

श्री राजेश ऋषि : डीईआरसी के माध्यम से दिल्ली में जो इस समय रेट कम हुए हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो केन्द्र सरकार की साजिश है। क्यों न वे इंतजार कर लें सीएजी के आडिट का। ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाये। क्योंकि सीएजी की आडिट रिपोर्ट दिखाती है आने वाली रिपोर्ट आपको दिशा देगी कि दिल्ली के अंदर रेट पहले से भी और कम किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए हो गया।

श्री राजेश ऋषि : अभी राजेन्द्र गुप्ता जी ने जो बताया कि अरूण जेतली जी ने 500 करोड रुपये पानी के लिए और 200 करोड रुपये इलैक्ट्रिक के लिए, रिफोर्म के लिए दिये थे। मैं चाहता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमें कहीं कोई रिफोर्म नजर नहीं आ रहे। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं ओम प्रकाश जी को कि ओम प्रकाश जी मैं जनकपुरी से आता हूं और जनकपुरी में जहां हमारे पहले विपक्ष के नेता रहे हैं कभी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्हीं के क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत दिक्कत रही, इतने दिनों उन्होंने राज किया और उनके वहां डेढ़ घण्टे पानी मिलता था आज की स्थिति ये है कि वहां चार घण्टे सुबह और दो घण्टे शाम को पानी मिलता है और बिना मोटर के पानी वहां चढ़ता है। हमारे वहां एक सात साल से यूजीआर बना हुआ था जो राजनीति की भेंट चढ़ा था। हमारी सरकार बनते ही हमने डेढ़ से दो महीने में उसको शुरू किया। आपको एक चीज और बता दें।

हमारे वार्ड महावीर एंकलेव पार्ट-1 पार्ट-2 पार्ट-3 आज पानी से लबालब हो चुके हैं। वहां बिना मोटर के लोगों के तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ता है। वहां टैंकर की राजनीति समाप्त हो चुकी है। आज जनता बहुत सुखी है वहां पर। दुखी हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी। जरा शार्ट में रखें सभी साथी।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया लेकिन थोड़ा बोलूंगा, माफी चाहूंगा कोई थोड़ा समय, माननीय ओम प्रकाश जी ने अभी बिजली और पानी की जो बात रखी कि पानी की कमी है, हां पानी की कमी तो हम स्वीकारते हैं, अभी भी कम से कम 200 एमजीडी पानी की कमी दिल्ली के अंदर है, इसको स्वीकारने में कोई हमें हर्ज नहीं क्योंकि अगर आप पिछले 20-25 साल में हालत ठीक नहीं कर सके तो हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं कि समर के अंदर दिल्ली में करीबन 1140 एमजीडी पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब करीबन 835 एमजीडी पानी का उत्पादन दिल्ली के अंदर हो रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री जी को, भाई कपिल मिश्रा को, जिन्होंने दिन रात एक करके और सभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, करीबन 48 से 50 एमजीडी पानी का उत्पादन पिछले चार महीने में दिल्ली में बढ़ाया और अगर इसका जीता जागता उदाहरण आप देखना चाहते हैं ओम प्रकाश जी, तो द्वारका का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसका एक जीता जागता उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं और ये बात मैं इस बात

को दम भरकर कह रहा हूं कि द्वारका में इस विधान सभा चुनाव से पहले जब फरवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभा की तो द्वारका को कहा गया कि मैं टैंकर वाली द्वारका में खड़ा हूं। हमने उस टैंकर वाली द्वारका का नाम बदलकर पानी का पाइप लाइन से एक-एक घर में एक-एक फलेट में पानी भेजने का कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय ओम प्रकाश जी को ये बताना चाहता हूं और खाली द्वारका ही नहीं, बवाना से हमारी कई सारी विधानसभायें जिसमें मुण्डका विधान सभा है, जिसमें करावला में दो एमजीडी पानी मिला, नजफगढ़ में पानी बढ़ा। जिस विधानसभा से मैं आता हूं मटियाला विधान सभा में एमजीडी पानी दिया गया जहां से 2 एमजीडी पानी द्वारका विधान सभा और पालम के अंदर भी भेजा गया। इन सारी विधान सभाओं में सभी विधायक गण यहां मौजूद हैं। इन सारी विधानसभाओं में पानी की स्थिति पहले से कहीं बेहतर है और ओम प्रकाश जी मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपके यहां पर पानी की स्थिति बहुत दयनीय है, बड़ी समस्या है तो इस सदन के बाहर भी आप कितनी बार अध्यक्ष साहब से मिले, चेयरमेन से मिले, माननीय मंत्री जी से मिले अपने क्षेत्र की पानी की समस्या को लेकर? या खाली आपने राजनीति की और अगर पानी की यहां पर इतनी समस्या है तो मैं दिल्ली के 70 विधायकों में से शायद सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे यहां पर पानी की इतनी ज्यादा यहां पर इतनी ज्यादा मौज है, पानी इतना ज्यादा है कि दो टैंकर मैं दो दिन बाद आपको देने की क्षमता रखता हूं आप बता दीजिए मैं आपको दो टैंकर और मैं आप ही को नहीं मेरे यहां पर 48 टैंकर हैं जिसमें से हमने दो वार्डों को टैंकर फ्री किया

पिछले एक महीने के अंदर। मैं आप तीनों ही साथियों को दो-दो टैंकर देने का वादा करता हूं मटियाला विधान सभा से।

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी शार्ट करिए प्लीज बहुत शार्ट करिए इसको।

श्री गुलाब सिंह : दूसरा मैं बिजली की अगर बात करें, आपको बताना चाहता हूं 2002 से पिछले 13 साल में पूर्व की किसी भी सरकार ने किसी भी बिजली कंपनियों के खिलाफ पेनल्टी जैसा कोई भी प्रावधान रखा ही नहीं और आज से कुछ दिन पहले बिजली कंपनियों ने खुद स्वीकारा है कि दिल्ली के अंदर बिजली की कमी नहीं है इनका इंफरास्टरकचर इतना घटिया, इतना दोयम दर्जे का है अगर आज किसी क्षेत्र के अंदर बिजली गुल हो जाये तो उसको रिकवर करके बिजली देने का इनके पास कोई भी प्रावधान नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि माननीय श्री सतेन्द्र जैन जी ने अभी जो पेनल्टी का प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं सरकार को जो अंडर सेक्शन 108 आपने लागू किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत की कड़ा कदम आपने बिजली कंपनियों के ऊपर उठाया है। लेकिन मुझे लगा पानी की समस्या है। सन् 2011 विजेन्द्र गुप्ता जी बाहर चले गये। सन् 2011-12 में मुझे एक बार इनके नेतृत्व में मैं छह महीने भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्त्ता रहा तो उस समय भी पानी की किल्लत थी तो जंतर-मंतर पर एक धरना करने के लिए चले गये थे। मेरे जैसे बहुत से युवा साथियों की टोली गयी विजेन्द्र गुप्ता जी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ मैं एक मटके का रंग लाल करके ले गया और मैंने उस मटके पर लिखा के "महंगा पानी सस्ता खून

सरकार कहां रही है घूम"। और मैं बड़े जोश के साथ तीन घंटे तक उस पोस्टर को और उस मटके को एक-एक हाथ में लेकर खड़ा रहा। कड़ी तपती धूप के अन्दर। एक भाजपा के साथी ने कहा इससे क्या हो रहा है? मैंने कहा जी आप भी तो धरने में शामिल हो, बोले यार धरने में तो हम इसलिए शामिल हैं कि फोटो खिचवाने हैं 2012 में निगम चुनाव आने हैं, टिकट के लिए लफड़ा हो रहा है, पानी किसको चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजनीति कर रहे हैं या वास्तव में पानी देना चाहते हैं? आप अगर इतने ही गंभीर हैं तो केन्द्र सरकार के माध्यम से हरियाणा सरकार को एक छोटा सा एक पत्र ही भिजवा दीजिये कि आप थोड़ा बहुत तो पानी छोड़ दीजिये। जैसे आपने पूर्व में चुनाव में कहा था ये बहुत गंभीर विषय है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की पहचान अपने कर्मों से है लेकिन अपना आखिरी वक्तव्य रखके मैं खत्म करना चाहता हूं। आपके नेताओं की पहचान मुझे लगता है कि पिछले 4 महीनों में जनता को लग रहा है कि हां, एक कर्मप्रधान वाली सरकार आयी है जो काम में विश्वास रखती है वर्ना इससे पहले ये पूर्व के नेताओं की पहचान ही यही हो गई थी के अगर गली में भैंस का कटरा भी मर जाता था तो नेता मौके पर जरूर पहुंचते थे, जाना चाहिए लेकिन पहचान कम से कम इस वहज से नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ मौकान ही जाता है। वहां कोई मर जाता था तो उसकी उसमें जाता है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में

अध्यक्ष महोदय : गुलाब जी शॉर्ट कीजिये, प्लीज।

श्री गुलाब सिंह : बस आखिरी बात कहके खत्म कर रहा हूं जी इन सारे

67 विधायकों की पहचान कर्म से है लेकिन उनकी पहचान बता रहा हूं। हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं तो वो अध्यक्ष जी अपने क्षेत्र में इतने पॉपुलर हैं कि अगर किसी के यहां कुतिया मर जाए तो भी जाएंगे, भैंस का कटरा मर जाए तो भी जाएंगे लेकिन पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो कभी नहीं गये। तो आपसे मैं देवरानी जिठानी भी लड़ती थी तो क्या कहती थी उनका नाम क्या था उनका नाम था नरेन्द्र सिंह। तो देवरानी जिठानी भी आपस में लड़ाई करती थी कि भगवान करे तुम्हारे घर में नरेन्द्र आये। तो यह पहचान बन गई थी आप लोगों की। इस पहचान को बदला आम आदमी के सारे विधायकों ने। यह पहचान हो गई थी आप लोगों की तो काम करने का हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है और जगदीश प्रधान जी मैं आपकी तरफ देखता हूं जब आप विजेन्द्र गुप्ता जी की तरफ देखते खड़े हुए थे...

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : बस जी बस एक लास्ट बात।

अध्यक्ष महोदय : न न अब समाप्त करिये प्लीज।

श्री गुलाब सिंह : आपको देख के ऐसा लगता है, कि देसी में एक कहावत है कि गब्बर फंस गया रांडां में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जहां तक पानी के संबंध में बात करना चाहता हूं कि हमारी जो विधानसभा करावल

नगर, जहां से हमारे जल बोर्ड के अध्यक्ष जी बैठे हैं, मंत्री जी और दूसरी विधानसभा उससे लगती हुई मुस्तफाबाद जहां से मैं मेम्बर हूं। एक तरफ भागीरथी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है और सोनिया विहार में मिश्रा जी के विधान सभा में एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है। जहां दो विधानसभाओं में दो प्लांट हों और वहां की जनता को पानी न मिले तो कितने शर्म की बात है। अभी मेरे कई साथियों ने कहा कि चौथी मंजिल पर पानी जाता है। मैं आपको दावा करता हूं कि जितनी भी हमारे यहां कॉलोनी हैं अगर एक मकान में भी बगैर मोटर के पानी आ रहा हो, तो मैं आज इस सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। इस तरह का यहां झूठ बोलना ख्वामखाह सरकार की इतनी तरफदारी करना, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। मिश्रा जी का एरिया करावल नगर का है। मेरा घर उसके अन्दर पड़ता है। हफ्ते में दो-तीन दिन पानी नहीं आता। चार दिन बाद आता है बड़ी मुश्किल से वो भी मोटर से खींचना पड़ता है। अभी कल मनोज तिवारी जी अपने यहां से सांसद है वहां यमुना विहार से के कई लोग आये कि जहां चौथी मंजिल पर पानी बगैर मोटर के चढ़ता था अब उनको दो-दो घंटे मोटर चलानी पड़ती है, तब जा के पानी ऊपर पहुंचता है तो अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पानी का जो हाल हमारी विधानसभा में या यमुना पार में है, मैं उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पानी के ऊपर ध्यान दिया जाए और पानी के स्रोत कहां से पैदा किये जाएं, उस पर चर्चा करानी चाहिए न कि तारीफ सुनने के बजाय चर्चा कराएं कि पानी के स्रोत कैसे बढ़े और दिल्ली को पानी कैसे मिले। दिल्ली के लोगों की प्यास कैसे बुझे। अभी हम पिछले हफ्ते रविपुरी में गये, जहां वाकई में देख के रोना आ रहा था कि वहां जो बीमार लोग हैं, अपाहिज हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है।

वो वहां मौत का इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी मौत आ जाए और हमें बुला लिया जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वहां पानी का इंतजाम नहीं है बोरिंग नहीं हैं वहां। वहां दस लाख रुपये देकर **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : भावना जी।

श्री जगदीश प्रधान : आप बैठिये नीचे बात सुनिये पहले। मैं बोलता नहीं हूं बीच में। आप सुनिये जरा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई, भावना जी। नहीं प्लीज।

श्री जगदीश प्रधान : मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पानी की जो दिल्ली में किल्लत है। ये नहीं मैं कहता कि आपकी सरकार चार महीने से है कि आप चार महीने में सारी दिल्ली की प्यास बुझा देंगे। इस पर चर्चा कराओ कि पानी का स्रोत कैसे बढ़े? कहां से पानी आए हमारे लिए? मैं आपके सामने सुझाव देना चाहता हूं कि जो यमुना बेल्ट है हमारी। वजीराबाद ब्रिज के पीछे का जो एरिया कई किलोमीटर का है, उसमें पानी का वॉटर ट्रीटमेंट लगाकर मतलब उसमें पानी स्टोर किया जाए ताकि दिल्ली के लोगों की प्यास बुझ सके। बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी नहीं मिलता है। लोग मोल लेकर पानी पीते हैं। तो यहां चर्चा करने से, वाहवाही करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं और अपनी समस्या उठाते हैं। पानी की समस्या पर कई साथियों ने कहा कि मेरे यहां पानी नहीं है। ट्रेफिक जाम की समस्या की भी यहां बात उठती है कि एक दुकानदार एक रेहड़ी लगवाता है पैसे लेकर। कोई उसके आगे खड़ी करवा देता है, वो ले रहा

है कि नहीं ले रहा, ये मिश्रा जी अच्छी तरह से जानते हैं खजूरी चौक की मैं बात कर रहा हूं। भजनपुरा चौक की मैं बात कर रहा हूं।

बिजली की बात है बिजली के दाम पर 51 परसेंट बिजली कंपनियों का शेयर है 49 परसेंट दिल्ली सरकार का शेयर है। जब आप आदेश करते हैं। आप सब्सिडी दे रहे हैं तो आपकी बात मान लें। सब्सिडी आप दे रहे हो। उनको आप आदेश कर सकते हो कि बिजली के रेट न बढ़ाये जाएं। डीईआरसी की बात करते हो इसमें जो 49 परसेंट का शेयर हमारा है दिल्ली सरकार का है, हमें बिजली कंपनियों की नकेल कसनी चाहिए। मीटर के नाम पर आज जो अंदर मीटर लगे हुए थे, आज उन्हें बाहर लगाया जा रहा है। किसी ने अगर कोई तार इसका छेड़ दिया, किसी शरारती आदमी ने उसका तार खेंच दिया तो उसके ऊपर केस बनाकर भेज देते हैं तेरा एक लाख की चोरी का केस बना दिया, या तो उनको 20 हजार रुपये देकर 10 हजार पेमेंट कर देंगे तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और जहां तक सदन के बर्बाद जो समय होता है यहां।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सिसोदिया साहब का और मुझे लगता है कि वे सदन में ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली की तकलीफ को समझते हैं और दिल्ली के दर्द को दूर करना चाहते हैं। मैं उनकी यहां तारीफ कर रहा हूं और यह बात नहीं है कि मैं किसी दबाव में कर रहा हूं। मुझे उनकी यह आदत अच्छी लगी है कि वे काम करना चाहते हैं और मैं उनका साथ देने के लिए 24 घण्टे तैयार हूं। अगर वह दिल्ली के विकास की बात करें। कुछ लोग यहां बैठकर...ओमप्रकाश जी बोल रहे थे यहां, उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी कि वह सीएम साहब के पास जाते।

अध्यक्ष महोदय : आप उस विषय को छोड़ दीजिए।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं कि सदन का समय बर्बाद न हो आगे, इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करें कि अपने विधायकों को या हमें भी बुलाकर एक ट्रेनिंग कैम्प लगायें, ताकि समय बर्बाद न हो। ओम प्रकाश जी का उसमें सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा...प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तब वे खड़े हुए। सदन के बारे में बात करनी थी या प्रधानमंत्री के बारे में...आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। पहले हमें यहां सदन देखना चाहिए। यहां के लोगों की आप सभी की जांच करवा लें। 70 के 70 विधायकों की करवा लें ताकि विवाद में रोजाना समय बर्बाद न हो, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, जैसे कि ओम प्रकाश जी ने बात शुरू की थी कि 'पानी माफ और बिजली हाफ'। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। हमारी सरकार ने जो कहा, सो किया और 5 दिन में पूरा किया। देर नहीं लगाई। 5वें दिन नोटिफकेशन जारी करके पानी को माफ कर दिया और बिजली को हाफ कर दिया। लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं दो चार बातें अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहूंगा और अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि आज तक बिजली कम्पनियों को इतना बड़ा बड़ा बजट दिया गया, अगर बात करें जब 49 दिन की हमारी सरकार के बाद भाजपा की सरकार जो केन्द्र में बैठी थी, वह सरकार चला रही थी। 1249 करोड़ रुपये दिल्ली की बिजली कम्पनियों को दिया गया, दिल्ली की जितनी भी व्यवस्था है, जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसको

अपडेट किया जाये। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी, उसके तीसरे दिन ही जब तूफान आया था तो इन बिजली कम्पनियों की पोल खुल गई थी। जब तीन दिन बिजली नहीं आयी थी। मैंने बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों के साथ बिजली घरों में जाकर दौरा किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो 34 बिजलीघर बाईपास थे। उनमें एसीबी आरएमयू पिछले कई सालों से सड़े हुए थे। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आपने ये क्यों नहीं बदले, इतना इतना बजट आपके पास होते हुए? उनके मुंह पर ताले लगे हुए थे। मैंने पूछा कि ये कितने सालों से खराब हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ये बता नहीं सकता। परन्तु जहां आप खड़े हैं, वह पिछले 6 साल से खराब है। तो मुझे हैरानगी हुई। हमने वॉलेन्टियर्स को लगाकर बाकी विधान सभाओं में भी चैक किया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जितने भी बिजलीघर हैं, उनमें कहीं न कहीं बिजली को डायरेक्ट किया हुआ था। आज जो बिजली इतनी ज्यादा जाती थी, उसका मेन कारण ही यही था कि जब एक गली में पहुंचता था, पहले एक टाइम था कि एसीबी गिर जाती थी और उस गली की सिर्फ लाइट बंद होती थी। बाकी एरिया की लाइट रहती थी। लेकिन वह पूरा बिजली घर डायरेक्ट होने की वजह से क्या दिक्कत आती थी कि पूरे का पूरा एरिया,... मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ओम प्रकाश जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आप बहुत जल्दी करते हैं। आप चिन्ता न करें। आपको पूरी जानकारी देंगे, खाना खिलाकर भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आज आपको जानकारी दे दें कि जहां जहां दौरा किया। अभी पिटीशन

कमेटी में सीईओ को बुलाया गया था। उनको वहां पर इन्ट्रोडक्टरी मीटिंग में समझा दिया गया था कि कहां कहां बदलाव चाहिए। आज दो किलोमीटर है, एलटी केबल आप जाकर देख सकते हैं, मायापुरी से लेकर जनकपुरी तक डाली जा रही है।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मंत्री आप है या वो हैं?

श्री जगदीप सिंह : सर, मैं मंत्री नहीं, मैं तो इस विधान सभा में एक छोटा सा सेवक हूं जो पूरी दिल्ली का ख्याल रख रहा हूं आपकी तरह।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। हम सदन चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम सीधे सदस्यों से बात कर रहे हैं। ये उचित है क्या?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, वो पिटीशन कमेटी की बात कर रहे हैं। आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, मेरी बात सुनिए। प्लीज ओम प्रकाश जी, विजेन्द्र जी, मुझसे बात कीजिए प्लीज। ये ठीक नहीं है मामला। आप उनको बोलने दीजिए। चलिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, प्लीज। सदन को चलने दीजिए। ये जल्दी समाप्त हो जायेगा। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी हैं। ये आप बीच में टोका टोकी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वहां पर बीच में टोका टोकी कर रहे हैं। दो मिनट रुक जाइये प्लीज।...नितिन जी, अनाथराइज्ड कॉलोनीज का बहुत बड़ा विषय है और उस पर चर्चा के लिए समय नहीं मिल पायेगा। मैं सदन से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस विषय पर...आप ये पूरा कीजिए।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली बार से इस बार भी अगर आप देखें तो बिजली का जो बिल्कुल कटऑफ सिस्टम है, बिल्कुल नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने तीनों कम्पनियों के बुलाकर आदेश दिए थे कि महंगी से महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। लेकिन बिजली के कटऑफ नहीं लगने चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आज कट ऑफ नहीं लगे हैं इस बार और जिस तरह से हम लोग पानी की बात कर रहे थे। पानी पर हमारी सरकार ने द्वारका, पालम, बवाना अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और इनको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा में एक गांव में जाकर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा, 27 साल से यहां पानी नहीं आया था, आज तेरी वजह से 27 साल बाद यहां पर पानी आया है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, आप बोलते जाइये, प्लीज। आप उधर ध्यान मत दीजिए। आप बोलिए प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हम टेंकर की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो 22-2200 टैंकर माफिया चल रहा था इनकी सरकारों के टाइम पर जो टैंकर का इतना बड़ा पूरा नेक्सेस चल रहा था, हमारी सरकार ने हर टैंकर पर जीपीएस सिस्टम लगाकर आज उससे पता चलता है। आप अपने मोबाइल पर देखकर बैठे बैठे यहां पर देखकर बता सकते हैं कि वह टैंकर कहां पर खड़ी है और कहां पानी देने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात और कह कर लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो सरकार आई है, ये कर्मयोगी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हम छोटी-छोटी बातों को...जिस तरह से ये लोग यहॉ नीचे बैठकर...

अध्यक्ष महोदय : आप उसकी चर्चा मत कीजिए। उसे रहने दीजिए। प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर वाकई जैसे अभी भी जगदीश प्रधान जी ने कहा है...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं रोक रहा हूं न जगदीश जी। मैंने रोका है उनको इमीजिएट रोका है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, आप ऐसे विषयों को न छेड़िए...

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपनी बात कह कर समाप्त कीजिए प्लीज।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कैसे बोल रहे हैं कि चर्चा करें। पानी पर चर्चा करें, जमीन पर चर्चा करें, बिजली पर चर्चा करें। हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोग इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वाकई कर्म से काम करना चाहते हैं। आज बिजली में सुधार लाये हैं, पानी में लाये हैं। बाकी चीजों के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग हमारा साथ दें बस। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहन बन्दना जी।

उपाध्यक्ष महोदया : अध्यक्ष जी, आपने बिजली पानी के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इस लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथियों ने बिजली हॉफ पानी माफ की बात कही उन्होंने। आज सुबह-सुबह हमारे घर पर एक सरकरी अधिकारी आए थे। उन्होनें बिजली के बिल 110/- रुपये और अच्छे पोस्ट पर हैं। और 65/- रुपया पानी का बिल, उन्होंने दिखाया। और यही बिजली हॉफ...आप क्षेत्र में नहीं घूमते, आपको पता नहीं है। जो बिजली हॉफ और पानी माफ कहते हैं, हमें क्षेत्र में घूमना चाहिए और हमारी सरकार के कार्य को जानना चाहिए। अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, टैंकर के बारे में जहां विधायक खड़े होते हैं, वहां टैंकर लगे होते हैं। टैंकर के बारे में ओम प्रकाश जी आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने जो टैंकर से काम

किया है और वो टैंकर कहां है, कब हैं, कितने बजे है, कितनी टाईमिंग है, और एक किलोमीटर उधर से इधर होगी तो उसके टैंकर को कैन्सिल भी किया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहां बैठे-बैठे अभी आपके गली मोहल्ले में कोई टैंकर आती हो जिसके बारे में आप सब को अगर पता करना है तो आपको पता हो जाएगी। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि किस गली में हमारा टैंकर आना है। क्योंकि आप अपने एरिया में नहीं घूमते। आप अपने क्षेत्र में घूमेंगे तब पता चलेगा कि वो टैंकर....

अध्यक्ष महोदय : बन्दना जी, बन्दना जी, आप दूसरे विषय पर आइए। छोड़िए प्लीज। ये आपसी तकरार को। मैं रोक रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : आपके कॉलोनी में पानी का टैंकर कब आ रहा है, नहीं आ रहा है इसके बारे में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से अलग में मिल लेना। समय सवा छह हो गया।

उपाध्यक्ष महोदया : इसको पता करने के लिए आपको पब्लिक मोनेटरिंग टेण्डर सर्विस पर जाना पड़ेगा और डीजेवी का जो जल बोर्ड का साईट है वहां पर जाकर आपको पता करना पडेगा।...**(व्यवधान)** और आपको पता चल जाएगा कहां पर और कब है। हमारी सरकार जो टैंकर माफियाओं के लिए जब जब काम किये 8 जून 2015 को एक ऑनलाईन पोर्टल लॉज किया गया। जिस में ऑन लाईन हम ट्रेकिंग कर सकते हैं। कि कहां पर हमारा टैंकर है। अभी यहां बैंठे-बैठे भी आप जानकारी ले सकते हैं। हम लोग पानी का प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ा रहे हैं अपने एरिया में 885 एमजीडी तक अब

तक पहुंच चुका है। 900 तक जिसको जाना था। वहां पर लक्ष्य हमारा था 900 और 885 एमजीडी तक हम पहुंच चुके हैं। टैंकर में जीपीआरएस सेंसर लगाया। जिसके लिए हम सब पूरे प्रयत्नशील है। और इसको हम लोग जो आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं चालू हुआ वो भी चालू हो चुका है। डिलेवरी पाईप। जो हमारा इधर उधर जाता था, उसे हम लोग मिस ट्रिप डिलिवरी पाईप में एक भी 100 मी से इधर-उधर कहीं भी जाएगा तो उसको हम लोग मिस ट्रिप मानते हैं। डिलिवरी प्वाईट से एक घण्टा पहले या एक घण्टा बाद पहुंचता है उसको भी हमारी सरकार मिस ट्रिप मानती है और इसके लिए अभी बहुत सारे साथियों ने कहा। आप सब जगदीश जी आप अपने इलाके में भी जो कह रहे है पानी नहीं आ रहा। हमारे एरिया में ऐसे-ऐसे इलाकों में पानी आया जहां बीस साल से कभी भी उस एरिया के साथियों ने मुंह नहीं देखा था पानी का। दूर-दूर तक जाना पड़ता था। वहां टैंकर एक दम टाईम से आप कभी भी सर्वे कर सकते हैं। डीडीए ने फ्लैट तो बनाए, बहुत सारे फ्लैट डीडीए ने हमारे एरिया में बनाए जहां पर आज भी पानी की सुविधा नहीं थी पहले और उसके तीन महीने के अन्दर आठ-आठ टैंकर एक कॉलोनियों में जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बन्दना जी शार्ट करिये प्लीज।

उपाध्यक्ष महोदया : मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जो सरकार ने इतने प्रयत्न करके इस कम समय में और इतनी अच्छी पानी की व्यवस्था और मैं आप सभी साथियों से कहती हूं जो आप सरकार के साथ बैठिए और देखिए कि कहां पानी नहीं आ रहा है। और पानी की अच्छी दुरूस्त

व्यवस्था करवाए। ये मत कहिए कि हमारे अन्डर में कुछ नहीं है। ये सीधे कह दीजिए जो हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने घर से निकल नहीं सकते। खाली सरकार की कमियां ढूंढने में न लगें। सरकार के साथ मिलके अपने एरिया के अपनी जनता जिसने आपको वोट दिया है उसको घर-घर पानी पहुंचाने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय : चलिए ठीक है बहन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में श्री राजेश गुप्ता जी। शार्ट करियेगा राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ता जी : अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा और कोशिश करूंगा जो भी बातें हो, वे रिपीट न हों। और विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे बोलने दे। उनमें से एक बात बोलना चाहूंगा। मैं अपने पावर मंत्री को इस बात पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने से दीन दयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर एक पावर ग्रीड सब स्टेशन का उदघाटन किया गया। इसमें मेरी थोड़ी सी विशेष रूचि इस लिए भी है क्योंकि मैं स्वास्थ्य का थोड़ा सा काम देखता हूं। तो इससे हमारे जो होस्पिटलस है जे.बी. पन्त, एलएनजीपी, मौलाना आजाद, जो मैडिकल कॉलेज है, उनको बहुत सारा पानी मिलने की पूरी सम्भावना है। सारी बिजली मिलने की पूरी सम्भावना है, जो बहुत जल्दी हो जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी ने इसके लिए जमीन भी मुहैया करा दी है। इसके आगे जो बिजली और पानी की सारी बातें यहां पर हो चुकी है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बिजली के रेट जिस तरीके से आधे किये गए और पानी के माफ किये गए इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो

दिखाया गया कि किस तरीके से दिल्ली की जनता खुश है और किस तरीके से बधाई की पात्र मानती है अरविन्द केजरीवाल जी को। बहुत ही अजीब मुझे जान की लगा मैं सिर्फ दो बात में एक बात पूछना चाहूंगा। सर प्लीज दो मिनट।. **.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी। दो मिनट प्लीज **....(व्यवधान)** उन्होंने यहीं बोला है पर ऐड दिखाया गया है।

श्री राजेश गुप्ता जी : अध्यक्ष महोदय, जो खरीदा हुआ ऐड है, ऐसी पार्टी हमें ऐड के बारे में बता रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। एक ऐसी पार्टी हमें ऐड के बारे में बता रही है जिसमें 11 में से 9 बार हमारे मुख्यमंत्री का उसमें नाम आया केजरीवाल-केजरीवाल। वो पार्टी बता रही है जिसने लगातार कहा कि इस बार मोदी सरकार, बीजीपी की सरकार नहीं कहा। हर-हर मोदी, घर-घर मोदी कर दिया। ये चाल चरित्र चेहरा मत दिखाइए। हमें बता रहे है कि हमें ऐड कैसे दिखानी चाहिए। इनमें 30 हजार करोड़ की इन्होंने ऐड दिखा दी और इनको सबसे अचम्भा इस बात का हुआ अध्यक्ष जी व्यवस्था**...(व्यवधान)।**

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी आप अपनी बात रखिए। प्लीज।**...(व्यवधान)**

श्री राजेश गुप्ता जी : अध्यक्ष जी। जो सबसे कमाल की बात है, इस संस्कृति कि इस संस्कृति के स्वयं के ठेकेदार फिलहाल ये पूछते हैं कि उसमें दिखाई गई महिला को यह कहते कि**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी : राजेश जी

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज मैं ये अल्पकालिक चर्चा में तीन विषय हम ले सकते थे। दो विषयों पर चर्चा पूर्ण हुई जिसमें लगभग 14 सदस्यों ने भाग लिया है। अनओथोराइज्ड कॉलोनिज का जो मुद्दा है जो मदन लाल जी ने रखा था, इस पर 6 सदस्यों ने भाग लेना है। इस विषय को लगभग सवा छह बज गए हैं। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी जो चर्चा हुई उस पर अपना वक्तव्य देंगे। मैं सदन से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस विषय को हम कल ले लें तो उचित रहेगा। आप की सहमति, इस पर सहमति है सबकी? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी।

उपमुख्यमंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है पिछले करीब दो घंटे से बहुत जरूरी मुद्दों पर सदन ने ध्यान दिलाया है। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि चर्चा और मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए एक मुद्दे पर क्योंकि सिर्फ औपचारिक रूप से बातचीत करनी हो तो फिर पांच मिनट बात करके खत्म की जा सकती है। चार लोग कुछ बोल लें बात खत्म हो जाती है। लेकिन अनोथराइज कॉलोनी भी बहुत अहम मुद्दा है और उस पर कल गंभीरता से चर्चा हो। मैं इस चर्चा को सुनते हुए अच्छा भी लग रहा था कि जरूरी मुद्दे पर बात हो रही है और साथ-साथ बार-बार एक बचपन में पढ़ी हुई कहावत भी याद आ रही थी "पीपल पात सरिस मन डोला"

...(व्यवधान)

उपमुख्यमंत्री : वो आएगी भी नहीं, कोशिश भी मत करिए, कोशिश भी ना करी जाए जिन्हें समझ में ना आए। वो कहावत है एक "पीपल पात सरिस मन डोला"। तो मन जो है चारों तरफ डोलता रहता है। मुद्दे चर्चा दिल्ली की

जरूरत कुछ भी हो, दिल्ली के मुद्दे हमने जो भी उठाने की कोशिश की हो, पर अपने पक्ष और विपक्ष दोनों के साथी कभी इस मुद्दे पर कूदेंगें कभी उस मुद्दे पर कूदेंगे

...(व्यवधान)

उपमुख्यमंत्री : अरे आप छोड़िए ना आपको समझ में नहीं आई तो काहे को बोल रहे है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी अब सुन लीजिए थोड़ी देर, ये अच्छा नहीं है।

उपमुख्यमंत्री : जिनको समझ में नहीं आई अध्यक्ष जी उनको रिकवेस्ट कर लें कि ना बोले। समझ में आ जाएगी तो कल भी बोल सकते है कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष जी, उनसे कहें कि कोशिश कर ले। कल तक समझ में आ सकती है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब मौका नहीं है। चर्चा उनकी तरफ से शुरू हुई थी। नहीं ओम प्रकाश जी, विजेन्द्र जी।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि बार-बार कभी एक मुद्दे पर, कभी दूसरे मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर 50 और मुद्दे डालकर, मुद्दे सारे जनता के हैं, मुद्दे सारे जनता के बीच के हैं और हम भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हुए है। सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सदन की विद्यत्ता वो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष बैठे हों, इससे पता चलती है कि जब हम एक मुद्दे पर गंभीरता से बात करें तो उस मुद्दे पर कितनी गहराई में करते हैं, इससे नहीं पता चलती कि इस मुद्दे पर

बात करते हुए हम कितने 50 और मुद्दों को वो चाहे कितने ही जरूरी हों और कितने ही गैर जरूरी हो। तो कहीं न कहीं उसका मुझे अभाव भी दिखा। इसलिए मैं एक शिकायत के लहजे में भी कह सकता हूं, पर ठीक है। अभी मैं पिछले 4-5 हफ्ते से बल्कि और कहे तो लगभग एक दो महीने से सोच रहा था कि दिल्ली नगर निगम में होता क्या है। क्योंकि दो मुद्दे उठे यहां पर दिल्ली नगर निगम का और बिजली पानी का। दिल्ली नगर निगम में होता क्या है। दिल्ली नगर निगम में एक पार्टी है, जो इसको चला रही है, सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पर। करते क्या है ये लोग, मैं सोच रहा था। आज पता चला कई साथी विधायकों ने बताया, यहां सदन के सामने रखा क्या है। अब उन्होंने बताया तो अपने किसी अनुभव के आधार पर ही बताया होगा। लोगों से उनको फीड बैक मिली है उसके आधार पर ही बताया होगा। मैं मानता हूं कि जो घटनाक्रम वो देख रहे होंगे, जो उन तक सूचनाएं पहुंच रही होंगी क्योंकि मेरी समझ में, एक मंत्री होने के नाते मैं देखता था तो नगर निगम मुझे दो ही काम करते हुए नजर आते थे। नगर निगम के नेता मुझसे बीच-बीच में मिलने भी आते थे या तो दिल्ली सरकार को बुरा भला कहने में या फिर दिल्ली सरकार से पैसे मांगते रहने में। मैं सोचता था कि दिल्ली नगर निगम के नेता जो वहां सत्ता में हैं, उनके पास कुछ और भी काम हैं। आज विधायक साथियों ने बताया कि वो किस काम में लगे हुए हैं। आज समझ में आया। तो अच्छा है, ये भी सदन की रिकार्ड में आया कि आखिरकार नगर निगम में अगर तनख्वाहें नहीं मिल रही तो नगर निगम का नेतृत्व कहां व्यस्त है। जिस नगर निगम के नेतृत्व को, जिन लोगों को जनता ने वहां चुनकर भेजा था कि जाइये इस लोकल बॉडी को नेतृत्व दीजिए, वो वहां तनख्वाह नहीं दे पा रहा, वो कोई विजन नहीं, मैं मैंने तो

पूछा था अध्यक्ष जी, नगर निगम के नेताओं से रिक्वेस्ट करके उनसे भी पूछा था, उनके अधिकारियों को बुलाकर भी पूछा था कि भाई, ये हमेशा दिल्ली सरकार से ही पैसे मांगते रहोगे या कुछ और विजन भी लेकर आओगे। जिस-जिस को मैंने पूछा कि भैया, कोई विजन है। चलो ठीक है इतने दे देंगे और इतने भी दे देंगे। चलो एक्सट्रा भी दे देंगे। चलो पुराना कर्ज जो पुरानी सरकारों के समय से था, इस बार इस मद से नहीं काटेंगे वो भी मान ली। अब ये बताओ कि इतने सारे कर्मचारी, इतने सारे काम चलाओगे कैसे, नगर निगम चलेगा कैसे इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है, इसका कोई विजन नहीं मुझे देखने को मिला अब तक...**(व्यवधान)**

उपमुख्यमंत्री : हां बता रहे है। फाइनेंस कमीशन पर भी आएंगे **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, ये उचित नहीं है। देखिए मैं बार-बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय उनको कहने दीजिए, उनका काम है, उनको वैसे भी समझ में नहीं आना, उन्होंने डीक्लेयर कर ही दिया कि...**(व्यवधान)**

उपमुख्यमंत्री : मैं जिस-जिस को समझ में आए उसके लिए सूचित करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जो लोग नगर निगम चला रहे है, अगर उनसे नगर निगम नहीं चलता तो इस्तीफा दे दें। हम दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम को चलाकर भी दिखा देंगे, घाटे से उबारकर भी दिखा देंगे, उसके

लोन पूरा करके भी दिखा देंगे और एक-एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह देके भी दिख देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमको विजन आता है, हमको नगर निगम चलाना आता है। हम नगर निगम भी चलाकर दिखा देंगे, हम दिल्ली सरकार चला रहे हैं। हम वहां का कर्ज भी माफ करवा देगें। हम वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह भी दिला देंगे। एक बार वहां बैठी हुई सत्तारूढ़ पार्टी जरा दिल दिखाकर कहे कि हमें चलाना नहीं आता, हमारे पास नगर निगम को कोई विजन नहीं है। उनके पास अगर कोई विजन नहीं है तो ये बात वो खुलकर कहें। तो अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार

...(व्यवधान)

उपमुख्यमंत्री : देखिए सच ऐसे ही कड़वा लगता है अध्यक्ष महोदय। जब नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठते हैं तो ये सवाल, तो ये गुमराह और ये सब शब्द आते हैं कोई बात नहीं। नगर निगम को हम जितना दे सकते हैं, हमने पूरी क्षमता से ज्यादा दे रखा है। पहले भी दिया था। सफाई कर्मचारियों की चाहे और मैंने सबूत भी रखे थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने सबूत भी रखे थे कि किस तरह नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह काट-काट कर स्विमिंग पुल पर पैसा खर्च किया गया। नगर निगमक के बजट में पेज न. सहित मैंने सबूत रखे हुए हैं। नगर निगम की कर्मचारियों की तनख्वाह काट-काट कर के विधायक फंड और वहां पर बेईमानी का रास्ता खोला गया, मैंने इसके भी सबूत रखे है यहां पर और बजट के पेज संख्या सहित रखे हैं। जिस वक्त अधिकारियों ने बजट बनाकर रखा, नगर निगम के नेताओं के पास न तो समझ थी, न विजन था, न नीयत थी। इसलिए आज वहां सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, अध्यक्ष जी। सीधी सी बात है। दूसरी बात

...(व्यवधान)

उपमुख्यमंत्री : तो अध्यक्ष महोदय नगर निगम के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो यहां साथियों ने रखा है कि आज नगर निगम के पास दुर्भाग्य से ऐसा नेतृत्व बैठा है जिसके पास ना विजन है, ना इच्छाशक्ति है, ना ईमानदारी है। तो अभी अगर उनसे नहीं चल रहा है तो चला लेंगे। या तो चला के दिखाए, विजन ला के दिखाए या छोड़ दे। कोई और चला लेगा। दिल्ली की जनता किसी ओर को ले लेगी।

दूसरा मुद्दा यहां बिजली पानी का उठाया गया। अध्यक्ष महोदय, बिजली पानी के मुद्दे पर बीच-बीच में मुझे लगा कई बार बहुत गंभीर मुद्दे उठे हैं और बिजली, पानी दिल्ली की जनता का ऐसा मुद्दा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सेकंड एक बात कहना चाहूंगा। बिजली पानी के मुद्दे में जगदीश प्रधान जी का जरा विशेष ध्यान रखें। उनकी विधानसभा में पानी की बहुत विशेष दिक्कत है।

उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ना सिर्फ जगदीश प्रधान जी की विधानसभा में बल्कि पूरी दिल्ली में पानी, बिजली एक समस्या है और मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि पिछले चार महीने में हमने दिल्ली को बिजली और पानी के आधार पर स्वर्ग बना के रख दिया है। ये कहना अतिशयोक्ति की भी अतिशयोक्ति होगी और ये कहना आधारहीन भी होगा। हम पूरी मेहनत से पिछले चार महीने से काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक मैं स्वयं दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन भी था और उस दौरान जिस तरह से 15-15 साल से रुके हुए, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्टस को खोला गया। वहां वाटर प्रोजक्टस को शुरू किया गया, reservoir को शुरू किया गया। वाटर प्लांटस चलाए

गए। वो एक सरकार की पिछले चार महीने की बड़ी उपलब्धियों में से है और उसकी वजह से यहां बैठे साथी कह रहे हैं और दिल्ली की जनता भी कह रही है, ऐसे-ऐसे इलाकों में भी पानी पहुंचने लगा है, जहां पहले नहीं पहुंचता था। पर निश्चित रूप से जो जगदीश भाई ने कहा और अन्य साथियों ने भी कहा कि पानी की दिल्ली में कमी भी है और जगदीश भाई की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक मूल मुद्दा उठाया। मुझे लगता है सबसे कोर core issue इश्यू ये है कि दिल्ली का अपना पानी का कोई स्रोत तो है नहीं। दिल्ली के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो भगवान से पानी मिलता है, प्रकृति से पानी मिलता है सबसे ज्यादा उसको संग्रह कैसे करके रखें। मैं नगर निगम के साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाजपा के साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नगर निगम में उनकी चलती है और अगर थोड़ा सा वहां से विजन मिले, थोड़ी इच्छाशक्ति मिले तो दिल्ली में वाटर बाडिज पर जिस-जिस ने जहां-जहां कब्जा करके रखा हुआ है फिर वो चाहे कोई पूर्व एमएलए हो या वर्तमान एमएलए हो, पूर्व पार्षद हो, मेयर हो, पार्षद हो कोई भी हो, वाटर बाडिज से उसके कब्जे हटाने में एक होकर साथ दिया जाए। भगवान का दिया हुआ पानी दिल्ली में खूब आता है। कई साल के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन इसमें नगर निगम, अध्यक्ष महोदय, यहां कहना बहुत आसान है जब नगर निगम से कहा जाता है कि वहां खाली करवाइए उस जगह को तो नगर निगम, करना तो वहां नगर निगम को है तो वाटर बाडिज को खाली करवाया जाए जो नगर के अधीन हैं। नगर निगम के कई पार्षदों ने भी ऐसी वाटर बाडिज पर कब्जा कर रखा है। उनको भी वहां से हटाया जाए। तो पानी का स्रोत जैसा मैंने कहा अपना कोई नहीं है। तो पानी के स्रोत या तो कुदरत

से आते हैं या पड़ोसियों से आते हैं दिल्ली में। तो वो पड़ोसियों से भी मदद कर करते हैं। जब पिछली बार चुनाव में उनकी पार्टी ने कहा भी था। उनकी पार्टी के पड़ोसी नेता ने जो वहां पड़ोसी राज्य में मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कहा था। बाद में कोर्ट में पलट गए, वो अलग बात है कि नहीं जी, हमने तो ये नहीं कहा था। पर फिर भी जितना भी पानी है उसको बैस्ट टैक्नालाजी करके, उसका बहुत इक्वल डिस्ट्रिव्यूशन ताकि सबको मिल सके, गरीब को भी मिल सके, अमीर को भी मिल सके, वेस्ट ना हो उस सबकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी बैस्ट टैक्नालाजी दुनिया में जो भी उपलब्ध है उनको लेके, जो सीवेज वाटर प्लांट है, सीवेज वाटर है, वेस्ट वाटर जिसको वेस्ट वाटर कहते है, हम कहते हैं उसको रिसाइकल वाटर, यूज्ड वाटर। यूज्ड वाटर को रिसाइकल करके मैक्सिमम इस क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है और हम बढ़ा रहे हैं उसको।

यही बात बिजली के संबंध में भी है। हमारा बिजली पर तो सबसे पहले कहना है कि बिजली कंपनियों में बहुत घपले हुए हैं और सीएजी की एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाए और लगातार सीएजी के संपर्क में हैं हम लोग। तो जांच जैसे ही पूरी होगी, मेरा पूरा भरोसा है कि बिजली ना सिर्फ सस्ती होगी बल्कि काफी सस्ती होगी और बिजली कंपनियों का घाटा जो दिखाया जाता है फर्जी, उसकी सारी पोल खुल जाएगी उसमें। बस मैं यही कहना चाहूंगा सदन के साथियों से कि जिन गंभीर मुद्दों पर आज हम चर्चा करने बैठे, उन पर थोड़ा और गंभीरता और गहराई से भी चर्चा करें और साथ-साथ निश्चित रूप से हम सरकार में बैठे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने हवा महल खड़े कर दिए हैं।

जैसे भी जिसके भी साथ मिलकर सहयोग, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे और यही डांट डपट भी ऐसी ही मिलती रहे यहां पर, बीच-बीच में मुद्दे पर जितनी गहराई चर्चा में मिलेगी उतना और सार्थक होगी जितना बिना मुद्दे के इधर उधर शोर मचेगा, चाहे इधर से मचे चाहे उधर से मचे उतना सदन का भी टाइम वेस्ट होगा और जनता का भी टाइम वेस्ट होगा। तय हमें हीं करना हैं, आपस में मिलकर करना है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, मुझे आपने मौका दिया बोलने का और अपनी बात रखने का, इस सदन में जवाब देने का। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार। अब सदन की कार्यवाही कल दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 24.06.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की गई)